

## मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से मौद्रिक नीति और चलनिधि परिचालन ने अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दिशा में काम कर ली है। प्रणाली को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अन्य नियामक व्यवस्थाओं, परिसंपत्ति वर्गीकरण यथावत, अस्थायी आस्थगन और पर्याप्त तरलता/चलनिधि के प्रावधान के साथ-साथ मौद्रिक नीति को लागू किया गया था। 2021-22 में, आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) में कमी जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कुछ उपाय पूर्व-निर्धारित, समापन की तिथियों के निकट पहुंच गए हैं, तरलता आंशिक रूप से समाप्त हो गई है किंतु इसका आधिक्य बना हुआ है, और नियामक उपायों को फिर से लागू किया गया है।

2019-20 और 2020-21 में कई बार रेट में कटौती के बाद, 2021-22 में रेपो रेट को 4 प्रतिशत पर बनाए रखा गया। हालांकि, प्रणाली में चलनिधि पूरे समय अधिशेष में रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रणाली में तरलता/चलनिधि प्रदान करने के लिए सेकेंडरी मार्केट जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम, विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन, तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध दीर्घकालिक रेपो परिचालन आदि सहित विभिन्न उपाय किए। इसके उपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिरिक्त तरलता की स्थिति का पुनः संतुलन करने के लिए परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो नीलामियों का भी उपयोग किया।

2021-22 में रिजर्व मनी और ब्रॉड मनी आपूर्ति वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। रिवर्स रेपो विंडो के अंतर्गत आरबीआई के पास बैंकों द्वारा बड़ी जमा राशि को दर्शाने वाले छोटे (समायोजित) मनी मल्टीप्लायर के कारण रिजर्व मनी वृद्धि पूरी तरह से ब्रॉड मनी आपूर्ति वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई। बैंक ऋण वृद्धि 2021-22 में धीरे-धीरे तेज हुई, जो अप्रैल 2021 की शुरुआत में 5.3 प्रतिशत थी। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 31 दिसंबर 2021 को बैंक ऋण वृद्धि 9.2 प्रतिशत थी। क्षेत्रीय स्तर पर, कृषि क्षेत्र ऋण में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई और उद्योग क्षेत्र में सुधार के संकेत मिले। हालांकि, सेवा क्षेत्र की ऋण वृद्धि अभी भी ठीक नहीं हुई है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित अग्रिम अनुपात 2017-18 के अंत में 11.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान शुद्ध गैर-निष्पादित अग्रिम अनुपात 6 प्रतिशत से घटकर 2.2 प्रतिशत हो गया। एससीबी का पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात 2013-14 में 13 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 16.54 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए संपत्ति पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न जून 2020 में सकारात्मक हो गया और मार्च 2016 से मार्च 2020 तक नकारात्मक लाभप्रदता अनुपात दर्ज करने के बाद सितंबर 2021 को समाप्त अवधि के लिए सकारात्मक बना रहा। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली ने अब तक महामारी के आर्थिक झटके को अच्छी तरह से झेला है, यद्यपि कुछ प्रभावों के आने में विलंब हो रहा है।

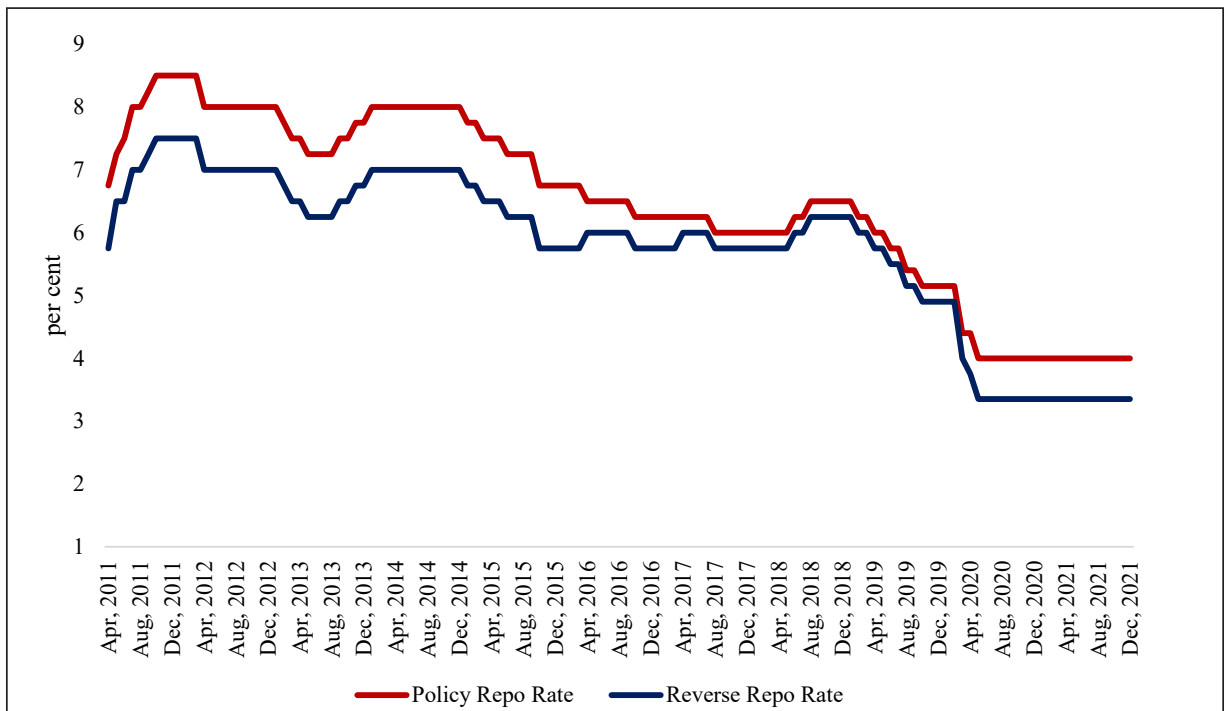
वर्ष 2021-22 अब तक पूंजी बाजारों के लिए एक असाधारण वर्ष रहा है। कई नए जमाने की कंपनियों/तकनीकी स्टार्ट-अप्स/यूनिकॉर्न्स द्वारा आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने में तेजी आई। अप्रैल-नवंबर 2021 में 75 आईपीओ इश्यू के जरिए 89,066 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो पिछले दशक में किसी भी साल की तुलना में काफी अधिक है। इससे पता चलता है कि 2021-22 में बाजार अब तक बैंकिंग पूंजी की तुलना में अधिक जोखिम वाली पूंजी लेता रहा है।

संसेक्स और निफ्टी 18 अक्टूबर, 2021 को 61,766 और 18,477 पर अपने चरम को छूने के लिए बढ़े। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय बाजारों ने अप्रैल-दिसंबर 2021 में साथी देशों से बेहतर निष्पादन किया। महामारी को देखते हुए निलंबित कर दी गई दिवाला प्रक्रिया मार्च 2021 के अंत में फिर से शुरू हुई। अप्रैल 2021 में शोधन-अक्षमता संहिता(आईबीसी) के अंतर्गत वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के रूप में कॉर्पोरेट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक प्री-पैकज दिवाला समाधान प्रक्रिया (PPIRP) प्रदान की गयी।

## मौद्रिक विकास

4.1 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी-मई 2020 के दौरान 115 आधार अंकों (बीपीएस) की सारवान कटौती करने के बाद, जोकि फरवरी 2019 से 250 संचयी आधार अंकों की कटौती है, अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान पालिसी रेपो दर की यथापूर्वस्थिति को बनाए रखा है (चित्र 1 और तालिका 1 देखें)। रेपो दर जो वर्तमान में 4 प्रतिशत है, पिछले दशक में सबसे कम है (चित्र 1)। मौद्रिक नीति के अकोमोडेटिव-स्ट्यांस(स्वरूप) के साथ और इस वायदे के साथ कि भविष्य में मौद्रिक नीति के इसी स्वरूप को जारी रखा जाएगा, मई 2020 से पॉलिसी दरों को रोका हुआ है, जहां यह दरें विकास को संधारणीय आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक समझी जाती हैं और मुद्रास्फीति को लक्षित/निर्धारित सीमा (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, +/- 2 प्रतिशत के एक बैंड के भीतर 4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति) में रखने को सुनिश्चित करती है।

तालिका 1: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रमुख दरों में संशोधन



**Table 1: Revision in Key Rates set by RBI**

प्रभावी तिथि	रेपो दर (प्रतिशत)	प्रति रेपो दर (प्रतिशत)	आरक्षित नकदी निधि अनुपात (निवल मांग और मीयादी देयताओं का प्रतिशत)	सांविधिक चलनिधि अनुपात (निवल मांग और मीयादी देयताओं का प्रतिशत)	एम एस एफ दर/बैंक दर (प्रतिशत)
06-02-2020	5.15	4.90	4.0	18.25	5.40
27-03-2020	4.40	4.00	4.0	18.25	4.65
28-03-2020	4.40	4.00	3.0	18.25	4.65
17-04-2020	4.40	3.75	3.0	18.00	4.65
22-05-2020	4.00	3.35	3.0	18.00	4.25
27-03-2021	4.00	3.35	3.5	18.00	4.25
22-05-2021	4.00	3.35	4.0	18.00	4.25
06-08-2021	4.00	3.35	4.0	18.00	4.25
08-10-2021	4.00	3.35	4.0	18.00	4.25
08-12-2021	4.00	3.35	4.0	18.00	4.25

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: एनडीटीएल: निवल मांग और मीयादी देयताएं

4.2 2021-22 की प्रारंभिक बैठकों में, एमपीसी ने विचार किया कि मुद्रास्फीति कुछ महीनों के लिए निर्धारित बैंड (टॉलरेंस बैंड) की ऊपरी सीमा से भी ऊपर मँडरा रही थी, लेकिन यह बहुत हद तक आपूर्ति में अचानक हुई कमी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण थी, जिसका अस्थायी होना अनुमानित था। समग्र मांग की सम्भावनाओं में प्रगामी सुधार हो रहा था किंतु क्षमता-उपयोग दरें अभी भी कम थीं। संपर्क-श्रमप्रधान(कॉन्टैक्ट-इंटेंसिव) सेवाएं पिछड़ रही थीं और पुनर्लाभ असमान था और यहां नीतिगत सहायता की आवश्यकता थी। दिसंबर 2021 में हाल की एमपीसी बैठक में, समिति ने बताया कि वैश्विक स्पिलओवर प्रभाव, कोविड -19 संक्रमण के फिर से फैलने और विश्वभर में अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कारक दबाव के बढ़ने मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों और उनके स्टांस(स्वरूप) में अपसरण जैसे कारणों से समग्र मांग की संभावना में अत्यधिक अनिश्चितता थी। तदनुसार, एमपीसी ने मुद्रास्फीति कारक दबावों की निगरानी जारी रखने, नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और अकोमोडेटिव-स्टांस(स्वरूप) के साथ बने रहने का निर्णय लिया।

4.3 2021-22 में अब तक, समग्र मौद्रिक और क्रेडिट की स्थिति अनुकूल रही किंतु मौद्रिक योग(एग्रीगेट) की वृद्धि दर - रिजर्व मनी, व्यापक-मुद्रा(ब्रॉड मनी) सहित पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। 7 जनवरी 2022 को रिजर्व मुद्रा(M0) में वर्ष-दर-वर्ष (YoY) 13 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड की गई, जबकि एक साल पहले यह 14.3 प्रतिशत थी। हालांकि, M0 में आरक्षित नगदी निधि अनुपात(CRR) में 'फर्स्ट राउंड इंपैक्ट' के परिवर्तनों के कारण वर्ष दर वर्ष 7.7 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड की गई जो कि एक वर्ष पहले 18.3 प्रतिशत की तुलना में थी (चित्र-2)।

4.4 आरक्षित नकदी निधि अनुपात(CRR) की चरणबद्ध पुनः बहाली के साथ जो कि 27 मार्च 2021 तथा 22 मई 2021 से प्रभावी है, 2021-22 के दौरान रिजर्व मुद्रा(M0) में विस्तार अब तक कंपोनेंट साइड की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकरों की जमा राशि से संचालित होता था द्य मुद्रासंचलन(CIC) में 7

जनवरी 2022 को 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो नकदी की ऐहतियाती मांग कम होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में कम है (तालिका 2)।

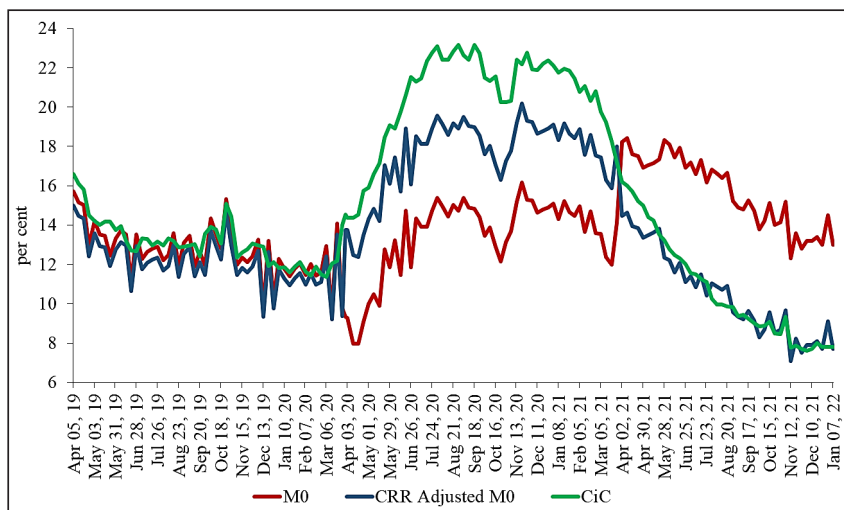
तालिका 2: मौद्रिक योग(एग्रीगेट) में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) (मार्च के अंत तक) (प्रतिशत में)

मद्	2015-16	2016-17 <sup>^</sup>	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
मुद्रासंचलन (CIC)	14.9	-19.7	37.0	16.8	14.5	16.6	7.8 <sup>#</sup>
बैंक में नकदी	6.6	4.2	-2.1	21.4	15.4	4.5	10.7
जनता के पास नकदी	15.2	-20.8	39.2	16.6	14.5	17.1	7.7
भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों का जमा	7.8	8.4	3.9	6.4	-9.6	28.5	42.0 <sup>#</sup>
मांग जमा	11.0	18.4	6.2	9.6	6.8	14.8	26.2
मीयादी जमा	9.2	10.2	5.8	9.6	8.1	10.9	8.2
रिजर्व मुद्रा (M0)	13.1	-12.9	27.3	14.5	9.4	18.8	13.0 <sup>#</sup>
व्यापक मुद्रा (M3)	10.1	6.9	9.2	10.5	8.9	12.2	9.9

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: <sup>^</sup>: 31 मार्च, 2017 रिजर्व मुद्रा(M0), मुद्रासंचलन (CIC) और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकों की जमा राशि (BD)को छोड़कर, \* : 31 दिसंबर, 2021 को, <sup>#</sup>: यथास्थिति 7 जनवरी 2022।

चित्र 2: रिजर्व मुद्रा (M0), आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) समायोजित M0 और CIC वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: CIC: मुद्रासंचलन, CRR: आरक्षित नकदी निधि अनुपात

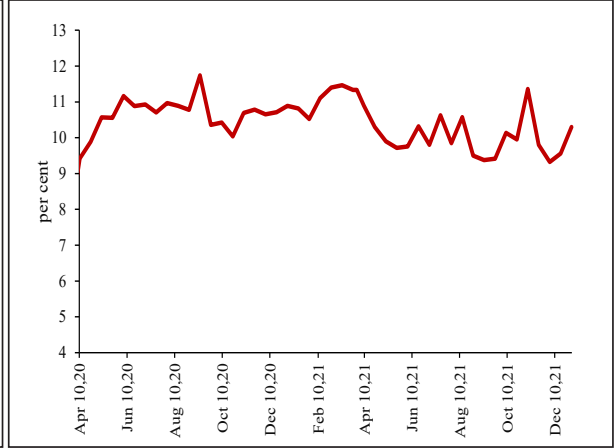
4.5 2021-22 में अब तक, व्यापक धन (M3) की सालाना वृद्धि 31 दिसंबर को 9.9 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले यह 12.5 प्रतिशत थी (चित्र 3)। कंपोनेंट साइड की ओर से एग्रीगेट जमा ने, जो कि सबसे बड़ा घटक है - वर्ष के दौरान अब तक M3 के विस्तार में सबसे अधिक योगदान दिया है (चित्र 4)। स्रोतों में, व्यापक धन (M3) में वृद्धि के लिए बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट एक प्रमुख योगदानकर्ता था। तरल और जोखिम मुक्त परिसंपत्तियों जैसे एसएलआर प्रतिभूतियों और सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के उच्च निवेश के परिणामस्वरूप सरकार को उच्च शुद्ध बैंक क्रेडिट मिला। स्रोतों की ओर से वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

भी M3 विस्तार के लिए पूरक बना। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि 31 दिसंबर 2021 को 9.2 प्रतिशत थी, जबकि एक साल पहले यह 6.6 प्रतिशत थी, जोकि क्रेडिट में तेजी को दर्शाता है। हालाँकि, समग्र क्रेडिट वृद्धि अभी भी पूर्व-महामारी स्तरों की तुलना में कम है।

चित्र 3: व्यापक धन वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



चित्र 4: सकल(एग्रीगेट)जमा वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

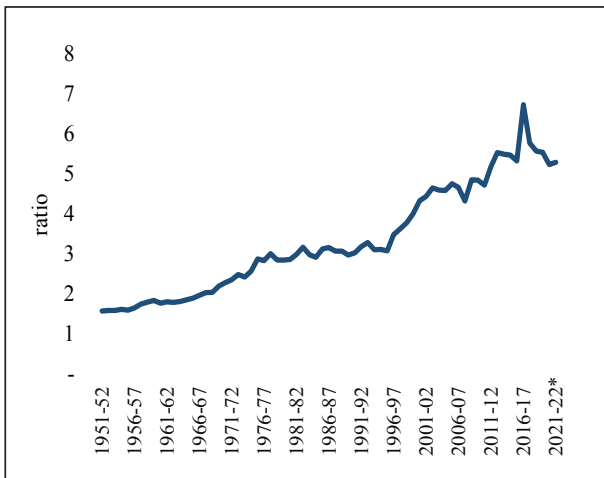


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

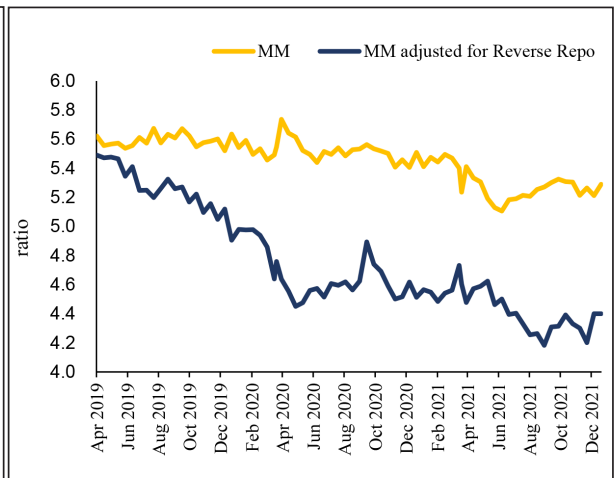
4.6 मनी मल्टीप्लायर(धन गुणक) इसको M3 और M0 के अनुपात के रूप में मापा जाता है,यह 2017-18 से गिरावट पर है (चित्र 5 (क))। 31 मार्च 2021 तक, मनी मल्टीप्लायर (MM) एक साल पहले 5.6 की तुलना में 5.2 पर रहा। हालांकि, रिवर्स रेपो के लिए समायोजित धन गुणक - विश्लेषणात्मक रूप से रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशि के समान - धन गुणक मार्च 2021 की समाप्ति तक 4.6 पर बहुत कम रहा। MM और समायोजित MM के बीच का अंतर भारतीय रिजर्व बैंक की रिवर्स रेपो विंडो के अंतर्गत बैंकों द्वारा धन की पार्किंग और कुछ हद तक कमजोर क्रेडिट निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। हालांकि, 31 दिसंबर 2021 को धन गुणक(MM), 5.3 तक का थोड़ा सुधार हुआ, जबकि समायोजित धन गुणक (MM) अभी 4.4 पर है(चित्र 5 (ख))।

चित्र 5: धन गुणक(मनी मल्टीप्लायर)

5(क)



5(ख)



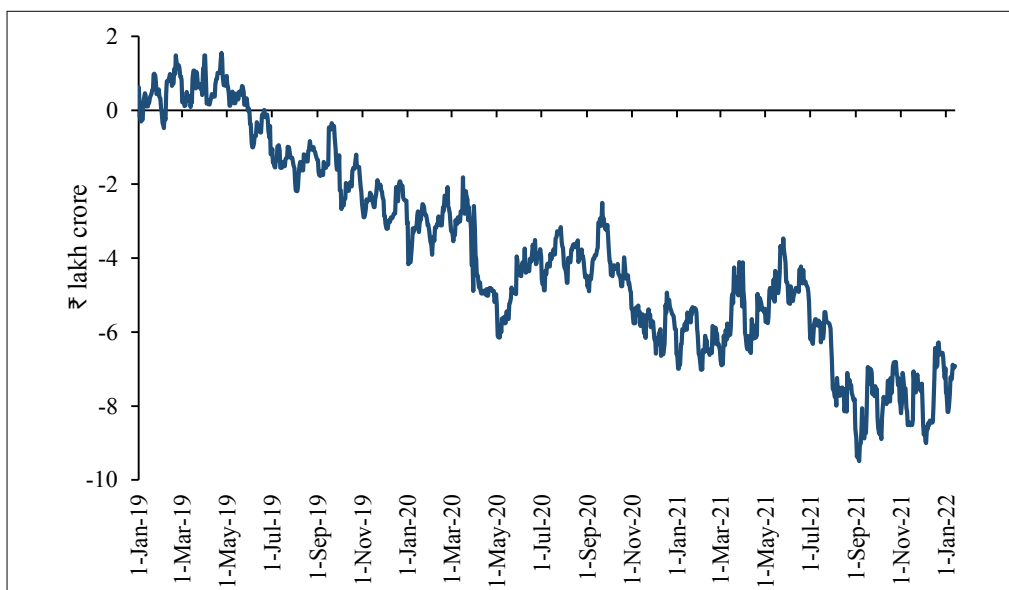
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: रिवर्स रेपो के लिए समायोजित धन गुणक आरबीआई के साथ वाणिज्यिक बैंकों के रिवर्स रेपो जमा के लिए समायोजित आरक्षित धन पर आधारित है। \* 2021-22 के लिए चित्र 5(क) में संख्या 31 दिसंबर 2021 तक है।

## चल निधि की स्थितियां और उसका प्रबंधन

4.7 मौद्रिक स्थितियां के समक्रमिक होने के साथ 2019 के मध्य से वित्तीय प्रणाली में चल निधि का अधिशेष बना हुआ है (चित्र 6)। कोविड महामारी के बाद 2020-21 में चलनिधि की स्थितियां में और ढील दी गई और आरबीआई ने तब से विकास का समर्थन करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त अधिशेष तरलता बनाए रखी है। 2021-22 में अब तक, रिजर्व बैंक, अकोमोडेटिव मौद्रिक नीति स्वरूप के सामंजस्य में वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त चल निधि सुनिश्चित करते हुए बाजार आधारित रिवर्स रेपो नीलामी (जैसे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR)) के द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत 'पैसिव अब्जॉर्प्शन' से फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो से चलनिधि/तरलता का पुनः संतुलन कर रहा है साथ ही इसने विकास को समर्थन देने के लिए एकोमोडेटिव मौद्रिक नीति स्वरूप के अनुरूप प्रणाली में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित की है। 2021-22 में चलनिधि की स्थिति अधिशेष में रही है।

चित्र 6: चलनिधि स्थितियां



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: ऋणात्मक चिन्ह अधिशेष चलनिधि को दर्शाता है। बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि कुल शुद्ध एलएएफ अवशोषण द्वारा सूचित की जाती है। इसलिए, कुल अवशोषण में वृद्धि का तात्पर्य अधिशेष चलनिधि/तरलता में वृद्धि से है।

4.8 2021-22 में प्रणाली को लक्षित चलनिधि/तरलता सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित उपायों को सम्मिलित किया गया है

- (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को ₹ 66,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं, जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) को ₹ 25,000 करोड़ ; राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) को ₹ 10,000 करोड़ ; और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ₹ 31,000 करोड़ समाविष्ट हैं।
- (ख) देश में कोविड से संबंधित हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को बढ़ाने के लिए ₹ 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी सुविधा;

- (ग) छोटे वित्त बैंकों के लिए ₹ 10,000 करोड़ की विशेष दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (SLTRO) योजना, जिससे उन लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं की सहायता की जा सके जो महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। विशेष दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (SLTRO) योजना को बाद में तत्काल उपयोग के लिए तैयार किया गया और इसे 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया।
- (घ) कोविड की दूसरी लहर में गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले संपर्क-श्रमप्रधान क्षेत्रों के लिए ₹ 15,000 करोड़ की तत्काल उपयोग की जा सकने वाली चल निधि को उपलब्ध करवाया गया।
- (ङ) तत्काल उपयोग के लिए तैयार लक्षित दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (TSLTRO) का विस्तार 31 दिसंबर 2021 तक किया गया।

4.9 इस अवधि के दौरान एक सेकंडरी मार्केट 'G-Sec एक्वीजीशन प्रोग्राम', G-SAP को, जिसकी घोषणा इस वर्ष पहले की जा चुकी थी, अधिशेष चल निधि से जोड़ दिया गया। G-SAP में सुविधाजनक चलनिधि स्थितियों के बीच "यील्ड कर्व" के एक स्थिर और व्यवस्थित विकास को सक्षम करने की दृष्टि से सरकारी प्रतिभूतियों की एक विशिष्ट मात्रा को खरीदने के लिए अग्रिम प्रतिबद्धता शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जी-एसएपी 1.0 के अंतर्गत ₹ 1 लाख करोड़ और जी-एसएपी 2.0 के तहत 1.2 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों (राज्य विकास ऋणों सहित) को खरीदा।

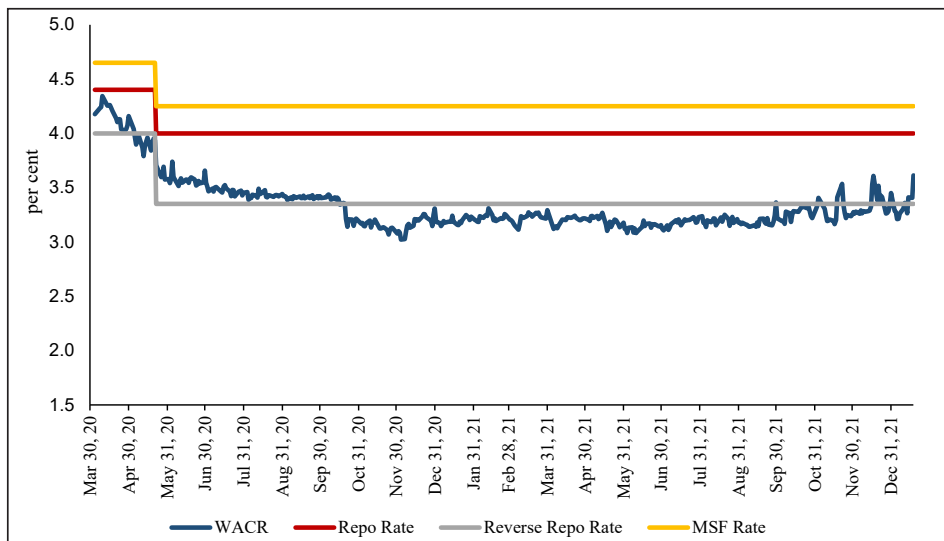
4.10 संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के साथ चलनिधि प्रबंधन कार्यों का क्रमिक सामान्यीकरण 2021-22 में चलनिधि प्रबंधन की प्रमुख विशेषता थी। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों को मुख्य संचालन के रूप में क्रियाशील किया गया था। इसके अलावा, मार्च 2020 में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंकों (बीपीएस) से घटाकर मई 2021 तक धीरे-धीरे 4 प्रतिशत के अपने पूर्व-महामारी स्तर तक बढ़ा दिया गया था। चलनिधि स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए, सितंबर 2021 से हर पखवाड़े में आयोजित मुख्य VRRR ऑपरेशन के अलावा अतिरिक्त रिवर्स रेपो नीलामियों का आयोजन किया गया था। दिसंबर 2021 के अंत तक 14 दिन के VRRR का आकार धीरे-धीरे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया। अब तक 2021-22 के दौरान, एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण 6.7 लाख करोड़ था।

4.11 अब तक 2021-22 के दौरान, मांग मुद्रा दर सामान्यतः रिवर्स रेपो दर से नीचे कारोबार कर रही थी, जो वर्ष के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर सीमा का निचला स्तर है (चित्र 7)। भारत औसत मांग दर (WACR) - जो मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है, उसने वर्ष के दौरान अब तक औसतन कॉरिडोर सीमा के न्यूनतम स्तर से 13 बीपीएस नीचे कारोबार किया है। ऐसा नवंबर 2021 में ही हुआ कि भारत औसत मांग दर (WACR) कॉरिडोर सीमा के भीतर थोड़ी चली गयी थी।

4.12 आरबीआई के बैंकों के लिए प्रमुख प्रतिपक्ष बनने के साथ, अंतर-बैंक व्यापार गतिविधि में कमी हुई और 'कॉल मनी मार्केट' की औसत दैनिक मात्रा दिसंबर 2021 में घटकर 9,077 करोड़ हो गयी, जो मार्च 2021 में 10,126 करोड़ रुपये थी।



चित्र 7: पॉलिसी कॉरिडोर सीमा और भारत औसत मांग दर (WACR)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड

### सरकारी प्रतिभूति बाजार में विकास

4.13 10-वर्षीय जी-सेक पर प्रतिफल (यील्ड) जो 26 सितंबर 2018 को 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गया था, जून 2020 में 5.75 प्रतिशत पर पहुँच कर पर्याप्त रूप से कम हो चुका था। तब से यह 31 दिसंबर 2021 तक बढ़कर 6.45 प्रतिशत हो गया है।

चित्र 8: भारत 10-वर्षीय जैनेरीक सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) प्रतिफल (यील्ड)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

4.14 वित्त वर्ष 2021-22 (चित्र 8) में रिजर्व बैंक के G-SAP द्वारा समर्थित 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति में ट्रेडिंग सकारात्मक नोट पर शुरू हुई, घरेलू स्तर पर अकोमोडेटिव-स्टांस (स्वरूप) जारी रहा और डोविश मौद्रिक नीति का स्वरूप दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाया गया। 2021-22 की पहली तिमाही (Q1) की शुरुआत में, 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ (यील्ड) 6.26 प्रतिशत था। मई 2021 में 10 वर्ष



का प्रतिलाभ(यील्ड) 5.96 प्रतिशत (इंट्रा डे) के निचले स्तर पर पहुंच गया। 4 जून 2021 को G-SAP 2.0 की ₹ 1.2 लाख करोड़ राशि की घोषणा और 15 जून 2021 को यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के निर्णय ने सुलभ-मौद्रिक(इजी मनी) नीति स्वरूप को जारी रखा जिससे प्रतिफल(यील्ड) 6 प्रतिशत के निकट रहा।

4.15 2021-22 की दूसरी तिमाही (Q2) की शुरुआत में प्रतिफल(यील्ड) बढ़ने लगा। 16 अगस्त 2021 को VRRR ऑपरेशन की मात्रा में चरणबद्ध वृद्धि की घोषणा और कुछ समय पहले ब्याज दर चक्र में बदलाव की संभावना से बाजार का रुझान(मार्किट सेंटीमेंट), "कीमत" की ओर अंतरित होगया, जिससे प्रतिफल(यील्ड) में कुछ बढ़ोत्तरी हुई और यह 6.26 प्रतिशत तक पहुंच गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लगातार निचले स्तर पर रहने, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम(G-SAP) नीलामियों में 10 वर्षीय बेंचमार्क पेपर के सम्मिलित किए जाने और 2021-22 की दूसरी छमाही के लिए सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त उधार नहीं लेने से प्रतिफल(यील्ड) को नियंत्रित रखने में सहायता प्राप्त हुई। दूसरी तिमाही के अंत में बेंचमार्क प्रतिभूति पर प्रतिफल(यील्ड) 6.22 प्रतिशत रहा। 2021-22 की तीसरी तिमाही(Q3) में, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण दिसंबर 2021 के अंत में प्रतिफल(यील्ड) बढ़कर 6.45 प्रतिशत हो गया।

4.16. यील्ड स्प्रेड (जिसे 10 साल और 1 साल के G-Sec यील्ड के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है) 2020 में तेजी से बढ़ा था, लेकिन 2021-22 में थोड़ा कम हो गया (चित्र 9)। हालाँकि, यह पूर्व-महामारी के वर्षों की तुलना में अभी भी बढ़ा है।

चित्र 9: 1-वर्षीय और 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति पर प्रतिफल यील्ड ( प्रतिशत में)



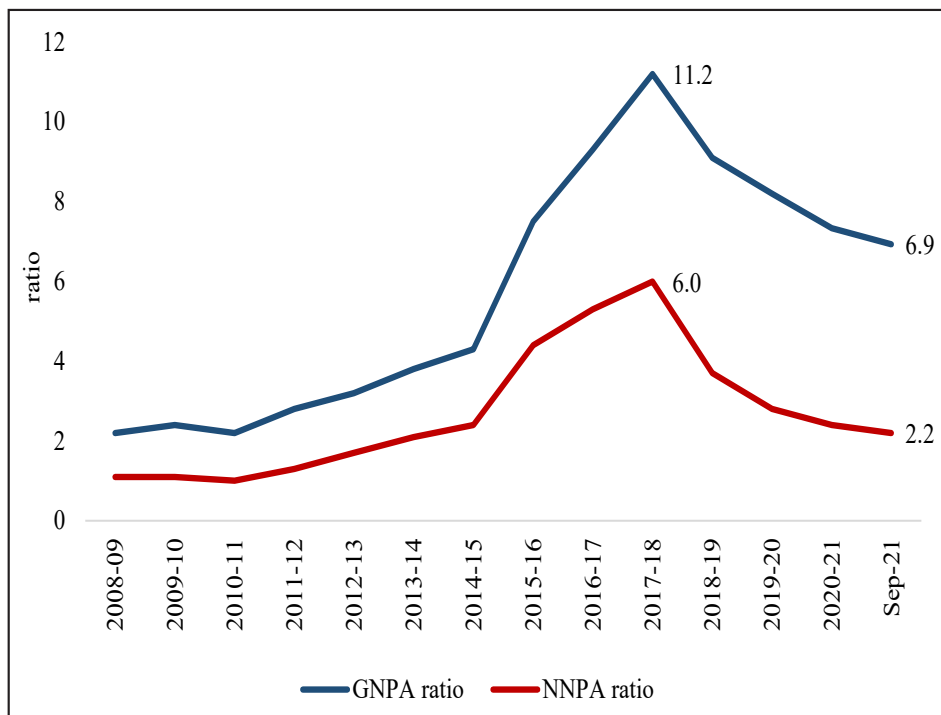
स्रोत: ब्लूमबर्ग

### बैंकिंग क्षेत्र

4.17 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों(SCB) के सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात (अर्थात सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए) और शुद्ध गैर-निष्पादित (एनएनपीए) अनुपात में 2018-19

से गिरावट जारी है। एससीबी का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.5 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) का एनएनपीए अनुपात सितंबर 2021 के अंत में 2.2 प्रतिशत था (चित्र 10)।

चित्र 10: जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: सितंबर 2021 की संख्या ऑफसाइट रिटर्न डेटा पर आधारित है

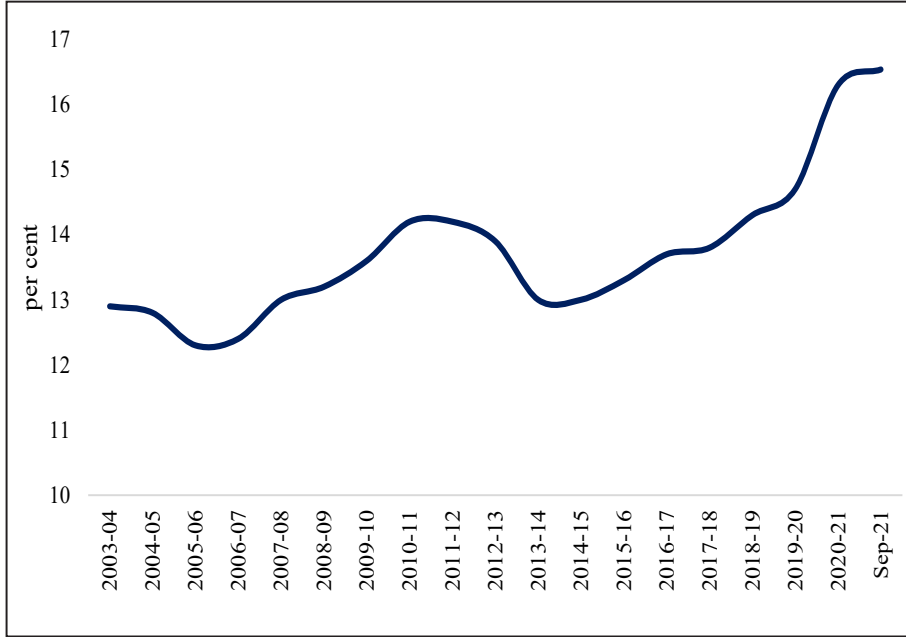
4.18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्चित मानक अग्रिम (RSA) अनुपात इसी अवधि के दौरान 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर, एससीबी का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 7.9 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 8.5 प्रतिशत हो गया। परिसंपत्ति गुणवत्ता के संबंध में प्रदान किए गए विभिन्न कोविड -19 संबंधित दंड से छूट / अधिस्थगन ने पुनर्निर्माण परिसंपत्तियों की वृद्धि में योगदान दिया और परिणामस्वरूप, बैंकिंग प्रणाली के लिए दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात सितंबर 2021 के अंत में बढ़ गया। कुल मिलाकर, ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकिंग प्रणाली ने महामारी के झटके को अच्छी तरह से झेल लिया है, यद्यपि कुछ प्रभावों के आने में विलंब हो रहा है।

4.19 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2020 के अंत में 9.4 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 8.6 प्रतिशत हो गया। पुनर्चित अग्रिमों में वृद्धि के कारण इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात मामूली रूप से 10.0 प्रतिशत से बढ़कर 10.1 प्रतिशत हो गया।

4.20 2015-16 से पूंजी पर्याप्तता अनुपात(CAR) में सुधार जारी है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों (तालिका 3) के सुधार के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों(SCBs) का जोखिम-भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात(CRAR) सितंबर-2020 के अंत में 15.84 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत तक 16.54 प्रतिशत हो गया। 2021-22 में जोखिम-भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात(CRAR)

के स्तर में सुधार सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने के साथ-साथ बाजारों से धन जुटाने के कारण हुआ, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक 'बाजार के स्रोतों' तैयार पूंजी का निरंतर उपयोग करते हैं (चित्र 11)। 30 सितंबर, 2021 को पूंजी की स्थिति के आधार पर, सभी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों ने पूंजी संरक्षण बफर(CCB) को 2.5 प्रतिशत से अधिक बनाए रखा।

चित्र 11: पूंजी पर्याप्तता अनुपात ( प्रतिशत )



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: सितंबर 2021 के लिए संख्या ऑफसाइट रिटर्न पर आधारित है

4.21 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों(SCBs) का आस्तियों/परिसंपत्तियों पर वार्षिक रिटर्न (ROA) सितंबर 2020 के अंत में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत तक 0.8 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान इक्विटी पर वार्षिक रिटर्न(ROE) 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.0 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए आस्तियों/परिसंपत्तियों पर वार्षिक रिटर्न (ROA) और इक्विटी पर वार्षिक रिटर्न(ROE) जून 2020 में सकारात्मक हो गए और मार्च 2016 से मार्च 2020 के दौरान नकारात्मक 'लाभप्रदता अनुपात' दर्ज करने के बाद सितंबर 2021 को समाप्त अवधि के लिए सकारात्मक बने रहे।

तालिका 3: NPA, CRAR, ROE और ROA - एससीबी, पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंक ( प्रतिशत )

अवधि	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक				सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				निजी क्षेत्र के बैंक			
	GNPA अनुपात	CRAR	RoE	RoA	GNPA अनुपात	CRAR	RoE	RoA	GNPA अनुपात	CRAR	RoE	RoA
Mar-19	9.07	14.32	-1.82	-0.15	11.59	12.2	-10.97	-0.66	5.25	16.07	5.49	0.60
Mar-20	8.21	14.78	0.78	0.07	10.25	12.85	-3.92	-0.25	5.45	16.55	3.20	0.35
Sep-20	7.49	15.84	7.68	0.64	9.39	13.51	4.33	0.26	4.93	18.21	10.04	1.10
Mar-21	7.33	16.30	7.64	0.65	9.11	14.04	4.63	0.28	4.94	18.42	10.01	1.14
Sep-21	6.93	16.50	9.04	0.79	8.57	14.4	8.47	0.52	4.73	18.65	10.01	1.17

स्रोत: ऑफसाइट रिटर्न, ग्लोबल ऑपरेशंस, भारतीय रिजर्व बैंक

4.22 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद लाभ) 2020-21 की पहली छमाही के दौरान 14,688 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 की पहली छमाही के दौरान 31,144 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ ₹ 32,762 करोड़ से बढ़कर ₹ 38,234 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का शुद्ध लाभ सितंबर 2020 के अंत में ₹ 59,426 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में ₹ 79,123 करोड़ हो गया।

#### बॉक्स 1: राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड

दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी), सरफेसी अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि सहित विभिन्न उपलब्ध समाधान तंत्र कुछ हद तक उपयोगी साबित हुए हैं, फिर भी पुरानी अनर्जक परिसंपत्तियों (NPA) का एक बड़ा भंडार है जिसको अभी तक हल नहीं किया गया है। इसके अलावा, जबकि भारत में 28 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (ARC) मौजूद हैं, सीमित पूंजीकरण और वर्तमान निवेश-सूची (पोर्टफोलियो) से कम वसूली के कारण, वे केवल छोटे मूल्य के ऋण प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। पुरानी अनर्जक परिसंपत्तियों (NPA) का समाधान करने और बैंकिंग प्रणाली का शोधन (CLEAN-UP) करने के लिए, केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा की गयी कि, “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के उच्च स्तर के प्रावधानीकरण के लिए बैंक बही-खातों का शोधन करने के उपायों की आवश्यकता है। मौजूदा दबावग्रस्त ऋण को समेकित करने और उसे नियंत्रित करने के लिए एक ‘एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड’ और ‘एसेट मैनेजमेंट कंपनी’ की स्थापना की जाएगी और इसके बाद अंतिम कीमतों की वसूली के लिए वैकल्पिक निवेश निधियों (AIF) और अन्य संभावित निवेशकों को परिसंपत्ति का प्रबंधन और निपटान किया जाएगा।”, इस दृष्टि के अनुरूप दो संस्थाओं अर्थात् नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL), और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) का गठन किया गया है।

एनएआरसीएल (NARCL) को 7 जुलाई 2021 को निगमित किया गया था और 4 अक्टूबर 2021 को एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एनएआरसीएल (NARCL) के प्रमुख रूप से स्वामी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों रहेंगे। केनरा बैंक 12 प्रतिशत तक की शेयरधारिता के साथ प्रायोजक है। एनएआरसीएल को विभिन्न बैंकों से इक्विटी और ऋण के संयोजन के माध्यम से पूंजीकृत किया जाएगा और इसकी अवधि 5 वर्ष होगी। यह 15:85 अनुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान विनियमों अंतर्गत विभिन्न चरणों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की तनावग्रस्त संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, जिसका अर्थ है कि अधिग्रहण के लिए नकद में 15 प्रतिशत और प्रतिभूति प्राप्तियों में 85 प्रतिशत होगा। IDRCL को 3 सितंबर 2021 को शामिल किया गया था और इसमें 1 निजी क्षेत्र के बैंकों का न्यूनतम 51% स्वामित्व होगा और शेष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास होगा।

NARCL और IDRCL के संबंधों को एक ऋण प्रबंधन समझौते के माध्यम से परिभाषित किया जाएगा, जहां NARCL तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को एकत्र करेगा और उनका अधिग्रहण करेगा और IDRCL, बदले में, NARCL को विशेष आधार पर तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन और समाधान सेवाएं प्रदान करेगा। IDRCL का कार्यकाल NARCL के साथ समाप्त होगा। एनएआरसीएल लीड बैंक को एक प्रस्ताव देकर परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगा और अग्रणी बैंक (एनएआरसीएल के) प्रस्ताव के साथ एक ‘स्विस चौलेंज’ प्रक्रिया चलाएगा जिसमें अन्य इच्छुक एआरसी / बोलीदाताओं को एनएआरसीएल द्वारा किए गए एंकर ऑफर को बेहतर बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एक बार एनएआरसीएल को पसंदीदा बोलीदाता के रूप में घोषित करने के बाद, एनएआरसीएल परिसंपत्ति अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करेगा और अंतर्निहित ट्रस्टों में संपत्ति का अधिग्रहण करेगा। परिसंपत्ति प्राप्त करने के बाद, आईडीआरसीएल प्रत्येक अंतर्निहित ट्रस्ट परिसंपत्तियों के लिए प्रस्तावित पुनर्गठन / समाधान योजना, रणनीति आदि तैयार करेगा और सुझाव देगा। एनएआरसीएल से संकल्प के अनुमोदन के बाद, आईडीआरसीएल संकल्प के कार्यान्वयन में भी सहायता करेगा। एआरसी के लिए आरबीआई के ढांचे के भीतर मौजूदा समाधान साधन (टूल) का उपयोग करके प्राप्त की गई परिसंपत्ति का समाधान किया जाएगा।

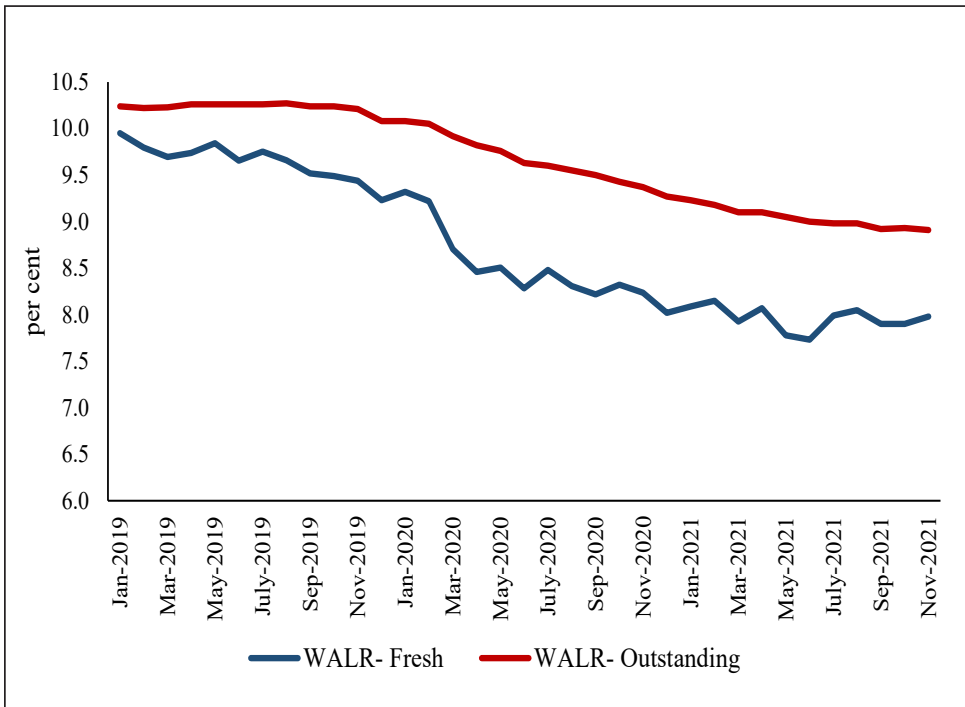
इस प्रकृति के समाधान तंत्र को आम तौर पर सरकार से बैंकस्टॉप की आवश्यकता होती है क्योंकि यह विश्वसनीयता प्रदान करता है और आकस्मिक बफर प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर, अन्य नियामक व्यवस्थाओं के साथ इक्विटी

के रूप में सरकारी भागीदारी के साथ बैड बैंक स्थापित किए गए हैं, उदाहरण के लिए, मलेशिया में दानहर्ता नैशनल बरहाद (दानहर्ता) या यूके में एसेट रेजोल्यूशन लिमिटेड (यूकेएआर)। इसलिए अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से नजीर लेते हुए, भारत में, सरकार ने 30,600 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान की है जो एनएआरसीएल(NARCL) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों(SR) को समर्थन देगी। सरकारी गारंटी 5 साल के लिए वैध होगी। इन प्रतिभूति रसीदों(SR) के लिए उपलब्ध गारंटी को वास्तविक वसूली और परिसंपत्ति के अंकित मूल्य के बीच की कमी को पूरा करने के लिए समाधान या परिसमापन पूरा होने पर लागू किया जा सकता है। गारंटी राशि एनएआरसीएल द्वारा अर्जित वास्तविक परिसंपत्ति के आधार पर जारी की जाएगी। यह व्यवस्था न केवल प्रतिभूति रसीदों के अंकित मूल्य की रक्षा करेगी बल्कि यह एनएआरसीएल के 100 प्रतिशत अपफ्रंट पूंजीकरण की आवश्यकता को भी दूर करेगी। सरकार उस राशि पर गारंटी शुल्क लगाएगी जिसकी वह गारंटी देती है, जो कि शीघ्र और समय पर समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए सालाना बढ़ेगी।

### मौद्रिक संचरण - बैंक ऋण और जमा दरें

4.23 भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2019 (वर्तमान सहजता चक्र) से रेपो दर में 250 बीपीएस की कमी की है। फरवरी 2019 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान रुपये के नए ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 197 आधार अंक और बकाया ऋणों पर 133 बीपीएस की गिरावट आई (चित्र 12)। बड़ी अधिशेष प्रणालीगत चलनिधि, अकोमोडेटिव-स्टांस(स्वरूप) के वायदे, चुनिंदा क्षेत्रों में ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए बाहरी बेंचमार्क प्रणाली ने मौद्रिक संचरण को सहायता प्रदान की।

चित्र 12: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत उधार दरें



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

4.24 अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, फंड-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1-वर्ष की औसत सीमांत लागत में 10 बीपीएस की गिरावट आई; बकाया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 19 बीपीएस की कमी हुई, हालांकि नए ऋणों पर इसमें 6 बीपीएस की वृद्धि हुई। बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 24 बीपीएस की कमी हुई (तालिका4)।

तालिका 4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की रेपो दर से जमा और उधार दरों में अंतरण( आधार अंक में बदलाव )

अवधि	रेपो दर	सावधि जमा दरें		उधार दरें		
		मेडियन टीडीआर - ताजा जमा	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा	1-वर्षीय औसत एमसीएलआर	डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर - ताजा रुपया ऋण
अप्रैल 2021- 2 नवंबर 2021	0	-1	-24	-10	-19	6
फरवरी 2019 - नवंबर 2021	-250	-213	-187	-155	-133	-197

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: डब्ल्यूएलआर: भारत औसत उधार दर। डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर; एमसीएलआर: फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर। टीडीआर: सावधि जमा दर।

4.25 समग्र मौजूदा मौद्रिक सहजता चक्र में निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संचरण थोड़ा अधिक रहा है, हालांकि यह अप्रैल-नवंबर 2021 में निजी बैंकों में अधिक था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बकाया रुपये के ऋण पर WALR 135 बीपीएस और निजी बैंकों के लिए 123 बीपीएस तक गिर गया, जबकि फरवरी 2019- नवंबर 2021 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ताजा रुपये के ऋण पर डब्ल्यूएलआर 210 बीपीएस और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 177 बीपीएस तक गिर गया(तालिका 5)। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बकाया रुपया ऋण पर डब्ल्यूएलआर 12 बीपीएस और निजी बैंकों के लिए 31 बीपीएस कम हो गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए डब्ल्यूएलआर 8 बीपीएस बढ़ गया।

तालिका 5: बैंक समूहों में संचरण ( आधार बिंदुओं में भिन्नता )

	फरवरी 2019 - नवम्बर 2021			अप्रैल 2021- नवम्बर 2021		
	डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर - ताजा रुपया ऋण	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा	डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर - ताजा रुपया ऋण	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	-135	-210	-168	-12	8	-21
निजी बैंक	-123	-177	-203	-31	-15	-32
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों	-133	-197	-187	-19	6	-24

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

रुएससीबी में सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक शामिल हैं

## बॉक्स 2: भारत में जमा बीमा

2021 में संसद द्वारा पारित जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम ने भारत में जमा बीमा के परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। डिजिटल इश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के कार्य DICGC अधिनियम, 1961 और DICGC सामान्य विनियम, 1961 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अधिनियम के अंतर्गत, बीमाकृत बैंक के जमाकर्ताओं को बीमाकृत जमा राशि का भुगतान करने के लिए निगम उत्तरदायी है। यह ऐसी देयता तब उत्पन्न होती है जब एक बीमाकृत बैंक निम्नलिखित से परिस्थितियों का सामना करता है: (i) परिसमापन (बैंक बंद होने पर सभी संपत्तियों की बिक्री), (ii) किसी योजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण या कोई अन्य व्यवस्था, (iii) किसी अन्य बैंक द्वारा विलय या अधिग्रहण। डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किया गया जमा बीमा सभी वाणिज्यिक बैंकों को सुरक्षा देता है, जिसमें भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी बैंक शामिल हैं। डीआईसीजीसी किसी बैंक को बैंकिंग लाइसेंस जारी होने पर तुरंत और स्वचालित रूप से बीमाकृत के रूप में पंजीकृत करता है। जमा बीमा प्रीमियम सभी बीमाकृत बैंकों के लिए अनिवार्य है और बैंकों द्वारा डीआईसीजीसी को भुगतान किया जाता है और जमाकर्ताओं से वसूल नहीं किया जाता है।

1961 में 1500 रुपये से शुरू हुआ जमा बीमा कवरेज (सुरक्षा) 1993 में धीरे-धीरे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद 2020 तक स्थिर रहा। केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषणा के बाद, जमा बीमा कवर को प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। प्रति बैंक 5 लाख रुपये प्रति जमाकर्ता के जमा बीमा कवरेज के साथ, 80 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में, मार्च 2021 के अंत में पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या (247.8 करोड़) कुल खातों की संख्या (252.6 करोड़) का 98.1 प्रतिशत थी। राशि के संदर्भ में, मार्च 2021 के अंत तक कुल बीमाकृत जमा (₹76.2 लाख करोड़) कुल निर्धारणीय जमा (₹149.7 लाख करोड़) का 50.9 प्रतिशत (घ 1 लाख कवर के तहत लगभग 30 प्रतिशत से ऊपर) था, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 20-30 प्रतिशत है। यह बैंक-समूह के अनुसार, कुल जमा की तुलना में बीमाकृत जमा राशियों का प्रतिशत आरआरबी के लिए 84 प्रतिशत, सहकारी बैंकों के लिए 70 प्रतिशत, एसबीआई के लिए 59 प्रतिशत, पीएसबी के लिए 55 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 40 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के लिए 9 प्रतिशत है। 31 मार्च 2021 तक, जमा बीमा की स्थापना के बाद से दावों के लिए 5,763 करोड़ की संचयी राशि का भुगतान किया गया है (27 वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में ₹296 करोड़ और 365 सहकारी बैंकों के संबंध में ₹5,467 करोड़)।

हालांकि, केंद्रीय बजट 2020-21 में फरवरी 2020 में घोषित बीमा राशि में वृद्धि के बाद भी एक सरोकार यह था कि जब आरबीआई द्वारा बैंक पर विभिन्न प्रतिबंध, जैसे स्थगन, आदि लगाए जाते हैं, तो वास्तविक जमाकर्ताओं को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जमा बीमा होने के बावजूद, बीमाकृत मूल्य की सीमा तक भी अपने स्वयं के धन का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 अधिनियमित किया गया था। संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं पे प्रकार हैं:

- पेश किया गया अंतरिम भुगतान : डीआईसीजीसी द्वारा उन बैंकों के जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान किया जाएगा जिनके लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई प्रतिबंध / अधिस्थगन लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं पर अपनी बचत तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- अंतरिम भुगतान की समय-सीमा: जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान प्रदान करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है। पहले 45 दिनों के भीतर, बीमाकृत बैंक को सभी बकाया जमाओं का विवरण निगम को प्रस्तुत करना होगा। विवरण प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, निगम दावों की प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा और सत्यापन के 15 दिनों के भीतर, निगम को ऐसे जमाकर्ताओं को भुगतान करना होगा।



- बैंकों द्वारा डीआईसीजीसी को पुनर्भुगतान
  - चुकौती का आस्थगन: डीआईसीजीसी के बोर्ड द्वारा तय की गई शर्तों पर, डीआईसीजीसी बीमा भुगतान के बाद एक बीमाकृत बैंक से इसके कारण पुनर्भुगतान को आस्थगित कर सकता है।
  - बैंक द्वारा डीआईसीजीसी को समय पर पुनर्भुगतान: डीआईसीजीसी (ब्याज और मूल राशि दोनों) को पुनर्भुगतान की प्राथमिकता स्थापित करने के लिए, अधिनियम में देरी के मामले में दंडात्मक ब्याज का प्रावधान किया गया है।
  - प्रीमियम की अधिकतम सीमा: पहले के अधिनियम में पहले प्रीमियम पर 15 पैसे की सीमा थी, जिसे हटा दिया गया है। अब, प्रीमियम की उच्चतम सीमा को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से डीआईसीजीसी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

अधिनियम के लागू होने के बाद से, जनवरी 2022 की शुरुआत तक, 1.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को उनके दावों के खिलाफ 1500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

## बैंक ऋण वृद्धि

4.26 2019 के बाद से ऋण वृद्धि में गिरावट आ रही है। अप्रैल 2021 की शुरुआत में ऋण वृद्धि 5.3 प्रतिशत थी और तब से बढ़ना शुरू हो गई थी, हालांकि यह अभी भी साधारण थी और 17 दिसंबर 2021 को 7.3 प्रतिशत थी। हालांकि, ऋण वृद्धि दिसंबर में तेजी से बढ़कर 31 दिसंबर को 9.2 प्रतिशत हो गई। 2021-22 में, जोखिम पूंजी (यानी पूंजी बाजार से जुटाई गई धनराशि) अब तक बैंकों की तुलना में पुनरुद्धार के लिए वित्त प्रदान करने में अधिक महत्वपूर्ण रही है (चित्र 13)।

चित्र 13: बैंक ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

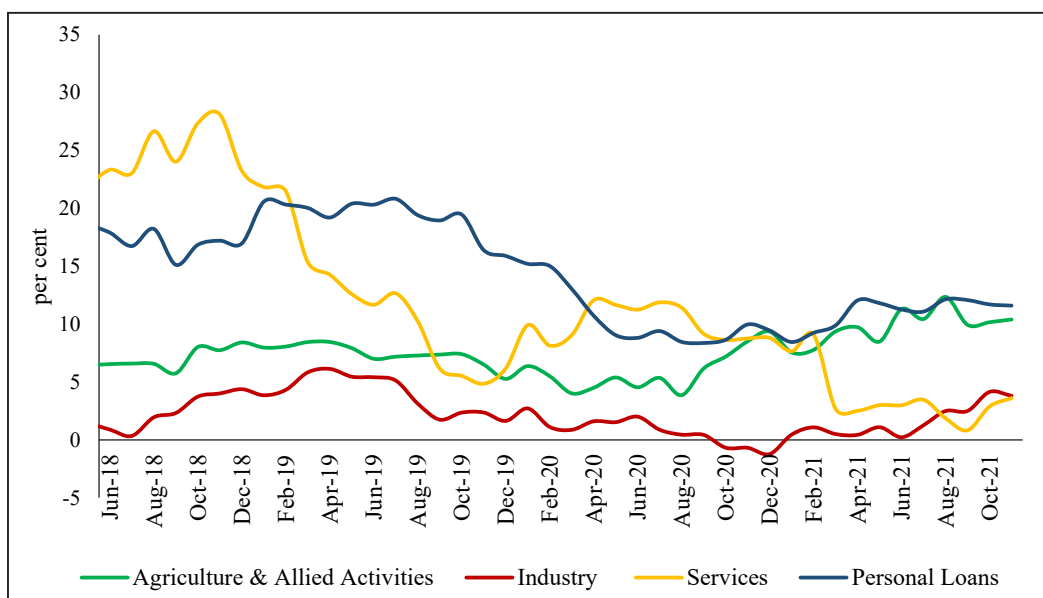
4.27 गैर-खाद्य बैंक ऋण<sup>1</sup> वृद्धि जो कि महामारी की अवधि के दौरान मौन रही और 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान 6 प्रतिशत से नीचे रही, इसमें धीरे-धीरे सुधार हुआ है और 31 दिसंबर 2021 को यह 9.3

<sup>1</sup> गैर-खाद्य ऋण वृद्धि की गणना धारा - 42 रिटर्न डेटा के आधार पर की जाती है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल होते हैं, जबकि क्षेत्रीय ऋण वृद्धि क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित होती है, जिसमें चुनिंदा बैंकों का लेखा-जोखा शामिल होता है, जो सभी अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत है।

प्रतिशत हो गई, पिछले वर्ष यह 6.6 प्रतिशत थी। यह वृद्धि व्यक्तिगत ऋण और कृषि क्षेत्र द्वारा संचालित थी। सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि में गिरावट जारी रही, हालांकि उद्योग को ऋण में सुधार के संकेत मिले।

4.28 कृषि के लिए ऋण में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, और नवंबर 2021 में 10.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी, जबकि नवंबर 2020 में 7 प्रतिशत थी। अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक अनुबंधित उद्योग के लिए ऋण वृद्धि जनवरी 2021 में सकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जुलाई 2021 से इसमें लगातार सुधार हो रहा है और नवंबर 2021 में यह बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया। मध्यम उद्योगों, विशेष रूप से, एक वर्ष से अधिक के लिए उच्च दो अंकों की वृद्धि देखी गई है और नवंबर 2021 में इस खंड में ऋण वृद्धि 48.7 प्रतिशत थी, जबकि नवंबर 2020 में यह 25.7 प्रतिशत थी। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण वृद्धि नवंबर 2021 में एक साल पहले के 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 12.7 प्रतिशत हो गई, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र को ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। बड़े उद्योगों को ऋण स्थूल रूप से पिछले वर्ष के समान स्तर पर ही रहा।

**चित्र 14: क्षेत्रीय ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)**



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

4.29 हालांकि, सेवा क्षेत्र की ऋण वृद्धि में अभी सुधार होना बाकी है। इस क्षेत्र में मंद ऋण वृद्धि लगभग सभी क्षेत्रों में धीमी वृद्धि के कारण थी। एनबीएफसी को बैंक ऋण में वृद्धि नवंबर 2021 में 5.2 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष में, एनबीएफसी ने आसान वित्तीय स्थितियों को देखते हुए सीधे धन और ऋण बाजारों से वित्त जुटाया। नवंबर 2021 में वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र में बैंक ऋण वृद्धि 0.4 प्रतिशत थी।

4.30 व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि पिछले वर्ष के 9.2 प्रतिशत की तुलना में नवंबर 2021 में बढ़कर द्वि-अंक में 11.6 प्रतिशत हो गई। आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण का सबसे बड़ा घटक, नवंबर 2021 में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वाहन ऋण की वृद्धि, व्यक्तिगत ऋण का दूसरा सबसे बड़ा घटक, नवंबर 2021 में 7.7 प्रतिशत हो गया, जो नवंबर 2020 में 6.9 प्रतिशत था (तालिका) 6)।

तालिका 6: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) (प्रतिशत)

क्षेत्र	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	नवंबर-20	नवंबर-21
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	3.8	8.5	4.0	9.4	7.0	10.4
<b>उद्योग</b>	0.7	5.8	0.9	0.5	0.7	3.8
सूक्ष्म और लघु	0.9	0.7	-0.6	2.8	0.6	12.7
मध्यम	-1.1	-2.0	-0.2	34.1	25.7	48.7
बड़े	0.8	7.1	1.1	-1.3	-0.4	0
<b>सेवाएं</b>	13.8	15.3	9.0	2.7	8.2	3.6
व्यापार	9.1	6.6	5.3	12.7	15.2	8.7
व्यावसायिक स्थावर संपदा	0.1	22.4	14.7	1.3	3.5	0.4
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	26.9	48.2	27.3	0.2	4.7	5.2
<b>व्यक्तिगत ऋण</b>	17.8	20.0	13.0	9.9	9.2	11.6
आवास (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	13.3	21.1	13.3	9.1	8.4	8.0
वाहन ऋण	11.3	23.7	7.2	6.2	6.9	7.7

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

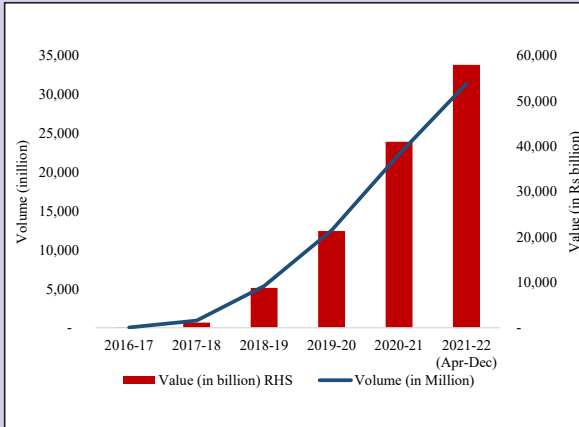
नोट: डेटा अनंतिम है और उन चुनिंदा बैंकों से संबंधित है जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत कवर करते हैं।

### बॉक्स 3: डिजिटल भुगतान

पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय लेनदेन में उच्च वृद्धि देखी गई है, जिसमें डिजिटल भुगतान करने के कई रास्ते हैं जो समय के साथ बढ़ रहे हैं।

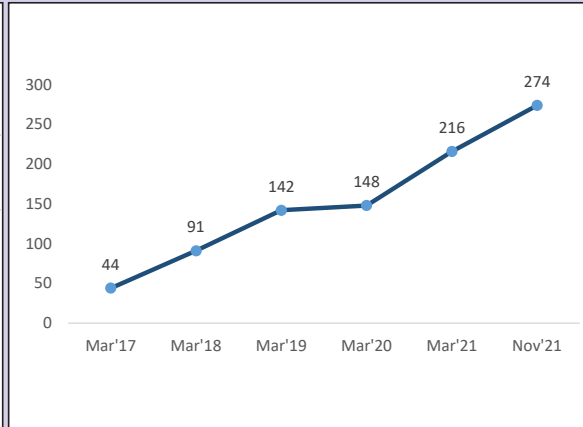
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) वर्तमान में लेन-देन की मात्रा के मामले में देश में सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली है, जो इसकी व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है (चित्र 3क और 3ख)। दिसंबर 2021 में, UPI (यूपीआई) द्वारा ₹ 8.26 लाख करोड़ के 4.6 बिलियन लेनदेन किए गए। UPI के शुरुआती उद्देश्यों में से एक कम मूल्य के लेनदेन के लिए नकदी की जगह लेना था। एनपीसीआई के विस्तृत लेनदेन डेटा के अनुसार, यूपीआई के माध्यम से 50 प्रतिशत लेनदेन ₹ 200 से कम के थे। 1 नवंबर 2018 को, सेबी द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए 'आईपीओ में भुगतान विकल्प के रूप में यूपीआई' को एक नए भुगतान चैनल के रूप में पेश किया गया था। अप्रैल-नवंबर 2021 में, UPI ने ₹ 44,381 करोड़ मूल्य के 24.26 मिलियन से अधिक वन टाइम मैंडेट क्रिएट ट्रांजैक्शन को संसाधित किया है। ऐसे लेनदेन के लिए लेन-देन की सीमा जिसे आरबीआई ने मार्च 2020 में 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया था, दिसंबर 2021 में इसे और बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने UPI और Pay Now को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की, जिसे जुलाई 2022 तक परिचालन के लिए लक्षित किया गया है। भूतान हाल ही में अपने क्यूआर (QR) कोड के लिए यूपीआई (UPI) मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। सिंगापुर के बाद मर्चेट लोकेशन पर भीम-यूपीआई (BHIM-UPI) को स्वीकार करने वाला यह दूसरा देश है।

चित्र 3क: यूपीआई (UPI) भुगतान



स्रोत: एनपीसीआई

चित्र 3ख: यूपीआई में बैंकों की संख्या



स्रोत: एनपीसीआई

तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) 24 X 7 X 365 उपलब्ध एक अन्य रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर प्लेटफॉर्म है। अप्रैल-दिसंबर 2021 में, IMP<sup>2</sup> पर ₹ 29,349 बिलियन के लेनदेन संसाधित किए गए हैं। 8 अक्टूबर, 21 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने (आईएमपीएस)IMPS लेनदेन की दैनिक सीमा ₹ 2 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख कर दी, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में और मदद मिलेगी।

अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया एक और डिजिटल भुगतान समाधान, e-RUPI एक व्यक्ति-विशिष्ट, और उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल वाउचर है, जहां ग्राहक के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है और बुनियादी फोन पर संचालित होता है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां इंटरनेट कनेक्शन की कमी है। e-RUPI के पहले उपयोग के मामले को कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए लागू किया गया था, जिसमें 2.2 लाख से अधिक लाभार्थियों को वाउचर जारी किए गए थे।

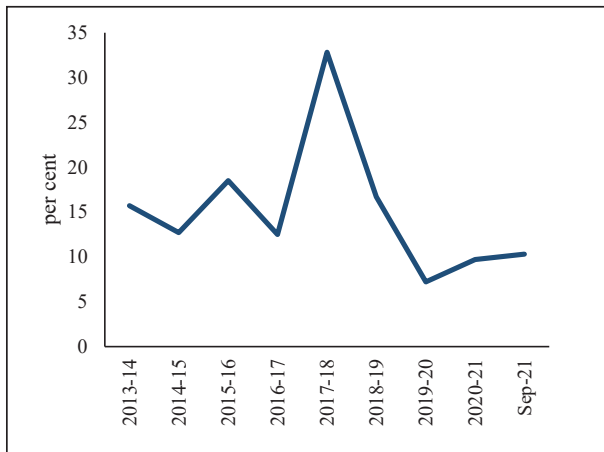
भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक, जो पूरे देश में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को दर्शाता है। सूचकांक में सम्मिलित हैं- (i) पेमेंट एनेबलर्स (वजन 25%), (ii) पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर - डिमांड-साइड फैक्टर (10%), (iii) पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर - सप्लाय-साइड फैक्टर (15%), (iv) पेमेंट परफॉर्मेंस ( 45%) और (v) उपभोक्ता केंद्रितता (5%)। डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2018 (आधार अवधि) में 100 से बढ़कर सितंबर 2021 में 304.06 हो गया।

### गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ( एनबीएफसी ) क्षेत्र

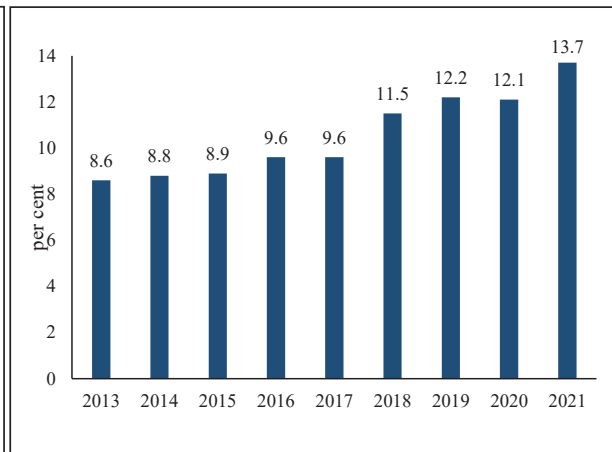
4.31 एनबीएफसी की ऋण वृद्धि अब तक 2021-22 में सुस्त बनी हुई है (चित्र 15)। एनबीएफसी क्षेत्र<sup>2</sup> का कुल ऋण मार्च 2021 में ₹ 27.53 लाख करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर सितंबर 2021 में ₹ 28.03 लाख करोड़ हो गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में एनबीएफसी क्रेडिट द्वारा मापी गई एनबीएफसी की क्रेडिट तीव्रता लगातार बढ़ रही है और यह मार्च 2021 के अंत में 13.7 पर रही (चित्र 16)।

<sup>2</sup> उनकी परिसंपत्ति के आकार के आधार पर यह क्षेत्र सितंबर 2021 तक शीर्ष 300 एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व करता है

**चित्र 15: एनबीएफसी से ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)**



**चित्र 16: जीडीपी अनुपात में एनबीएफसी का क्रेडिट**



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

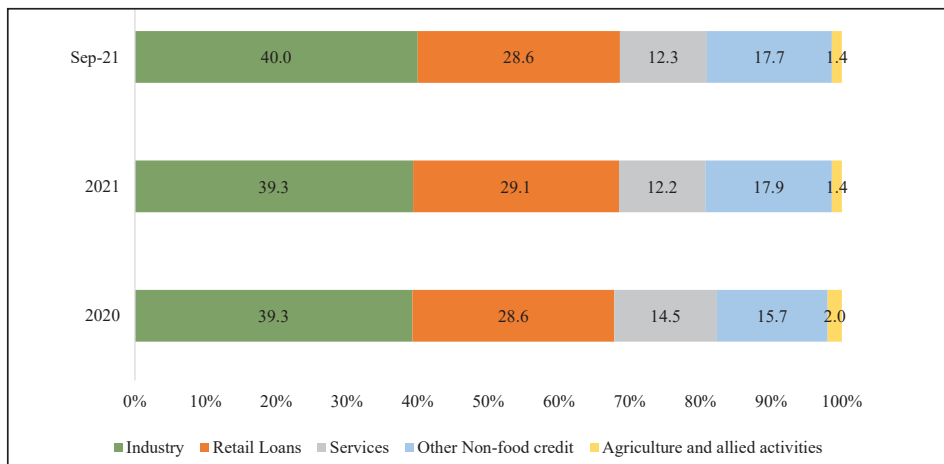
नोट: सितंबर 2021 का डेटा केवल जमा राशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी और ऑफसाइट रिटर्न डेटा के आधार पर जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी से संबंधित है।

स्रोत: भारत में बैंकिंग के स्वरूप और प्रगति, भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: डेटा मार्च के अंत में है; इस्तेमाल किया गया जीडीपी डेटा मौजूदा बाजार कीमतों पर जीडीपी है (आधार: 2011-12)

4.32 उद्योग एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा दिए गए ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, इसके बाद खुदरा ऋण और सेवाओं का स्थान रहा (चित्र 17)। एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा उद्योग को कुल ऋण में बढ़े उद्योग की हिस्सेदारी मार्च 2019 के अंत में लगभग 82 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में 90 प्रतिशत हो गई।

**चित्र 17: एनबीएफसी क्रेडिट का क्षेत्रीय वितरण**



स्रोत: पर्यवेक्षी रिटर्न, भारतीय रिजर्व बैंक।

नोट: 2020 और 2021 की संख्या मार्च के अंत के आंकड़े दर्शाती है। सितंबर 2021 के लिए संख्याएं भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2020-21 की सर्वेक्षण गणना हैं।

4.33 एनबीएफसी की कुल संपत्ति सितंबर 2020 में ₹ 36.37 लाख करोड़ से बढ़कर सितंबर 2021 में ₹ 42.05 लाख करोड़ हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 15.61 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई। एनबीएफसी में बैंकों का एक्सपोजर (बैंक लेंडिंग और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) में निवेश के रूप में) सितंबर 2020 में ₹ 8.44 लाख करोड़ से बढ़कर सितंबर 2021 में ₹ 9.16 लाख करोड़ हो गया, जो 8.5 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज करता है।

4.34 सुरक्षित और असुरक्षित उधार और सार्वजनिक जमा के रूप में एनबीएफसी की बाहरी देनदारियों में सितंबर 2021 में 7.95 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। जबकि अन्य वित्तीय संस्थानों से उधारी मार्च 2021 में ₹58,650 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर सितंबर 2021 में ₹59,525 करोड़ हो गई, (4.34 प्रतिशत सालाना वृद्धि) ,बाजार उधारी - एनसीडी और सीपी - सितंबर 2020 में ₹10.56 लाख करोड़ से बढ़कर सितंबर 2021 में ₹ 11.41 लाख करोड़ (8.09 प्रतिशत सालाना वृद्धि) हो गई।

4.35 एनबीएफसी का जीएनपीए अनुपात मार्च 2021 के अंत में 6.06 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2021 के अंत में 6.55 प्रतिशत से अधिक था। हालाँकि, उनका शुद्ध एनपीए अनुपात सितंबर 2021 के अंत में 2.93 प्रतिशत बना रहा। सितंबर 2021 के अंत में एनबीएफसी क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत की नियामक आवश्यकता के मुकाबले सीआरएआर 26.64 प्रतिशत था।

#### बॉक्स 4: भारत में फेक्ट्रिंग

‘फेक्ट्रिंग’ दुनिया भर में पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, खासकर एमएसएमई के लिए। फेक्ट्रिंग एक लेनदेन है जहाँ एक इकाई तत्काल धन के लिए अपनी प्राप्तियों (ग्राहक से बकाया) को तीसरे पक्ष (बैंक या एनबीएफसी की तरह एक ‘फेक्टर’) को बेचती है। प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर तुरंत पैसा प्राप्त करने के लिए सभी या कुछ इनवॉइस(बीजक) को एक फेक्टर को बेचा जा सकता है। फेक्टर तब माल के खरीदार से भुगतान एकत्र करता है और कुछ ब्याज के रूप में कमीशन अर्जित करता है छ यह बिल डिस्काउंटिंग(भुनाई) से अलग है। बिल डिस्काउंटिंग छूट में, बैंक या एनबीएफसी विक्रेता को बीजक के कुल बकाया मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत देता है और विक्रेता को खरीदार द्वारा बीजक के भुगतान की जिम्मेदारी लेनी होती है। हालांकि, फेक्ट्रिंग के मामले में, फेक्टर चालान के संग्रह की जिम्मेदारी लेता है। दो अलग-अलग प्रकार के फेक्ट्रिंग होते हैं: श्रमश्रय के साथ फेक्ट्रिंग जहाँ विक्रेता को माल के खरीदार द्वारा भुगतान करने में विफल होने पर कारक से प्राप्त अग्रिम का भुगतान करना पड़ता है, और शबिना सहारा फेक्ट्रिंग जहाँ माल के खरीदार द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में कारक डिफॉल्ट का जोखिम वहन करता है।

एमएसएमई(MSMEs) की चलनिधि/तरलता के मुद्दों को हल करने और भारत में फेक्ट्रिंग के लिए बुनियादी कानूनी ढांचे को निर्धारित करने के लिए, ‘फेक्ट्रिंग विनियमन’ अधिनियम 2011 को अधिनियमित किया गया था। फेक्ट्रिंग अधिनियम 2011 के अनुसार, चार प्रकार की संस्थाओं को फेक्ट्रिंग व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति थी: बैंक, सांविधिक निगम (जिन्हें धारा 5 के अंतर्गत पंजीकरण से छूट दी गई थी), एनबीएफसी (जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्राप्त करना होता है) और कंपनियां (जिन्हें धारा 3 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से विनिर्दिष्ट पंजीकरण प्राप्त करना होता है)। फेक्ट्रिंग अधिनियम 2011 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक केवल उन्हीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) का पंजीकरण करता है जो फेक्ट्रिंग को “प्रमुख व्यवसाय” के रूप में करते हैं, अर्थात् जिनकी फेक्ट्रिंग व्यवसाय में वित्तीय संपत्ति उनकी कुल संपत्ति का कम से कम 50 प्रतिशत है और फेक्ट्रिंग व्यवसाय से प्राप्त आय ,उनकी सकल आय के 50 प्रतिशत से कम न हो। इन उपबंधों के अंतर्गत, केवल 7 एनबीएफसी(कैनबैंक फेक्टर्स, इंडिया फेक्ट्रिंग एंड फाइनेंस, एसबीआई ग्लोबल फेक्टर्स, सीमेंस फेक्ट्रिंग, बिब्बी फाइनेंशियल सर्विसेज, आईएफसीआई फेक्टर्स और पिनेकल कैपिटल सॉल्यूशंस) को ही ‘एनबीएफसी-फेक्टर’ कहा जाता है और फेक्ट्रिंग व्यवसाय में थी। अधिनियम में एनबीएफसी पर इस ‘प्रमुख व्यवसाय’ प्रतिबंध ने फेक्ट्रिंग के दायरे को सीमित कर दिया था।

इस बीच, आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय संधारणीयता के लिए दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देने के लिए जनवरी 2019 में श्री यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समग्र रूप से एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अन्य सुझावों में, समिति ने सिफारिश की ,कि जिन एनबीएफसी का मुख्य व्यवसाय फेक्ट्रिंग है, उनके अलावा अन्य एनबीएफसी को भी फेक्ट्रिंग व्यवसाय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, फेक्ट्रिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को व्यापक रूप से यू.के. सिन्हा समिति की सिफारिशों के अनुरूप संशोधनों के साथ पारित किया गया था। किए गए प्रमुख परिवर्तन हैं:

- प्रमुख व्यवसाय मानदंड को हटाने से पात्र एनबीएफसी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो फेक्ट्रिंग व्यवसाय कर सकते हैं।
- इनवॉइस के पंजीकरण और उस पर प्रभार की संतुष्टि के लिए समय अवधि सरकार द्वारा नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और दोहरे वित्तपोषण के माध्यम से धोखाधड़ी को रोका जा सके।
- वर्तमान में, फेक्ट्रिंग या तो मैनुअल रूप से या ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)<sup>3</sup> पर की जाती है। अब, संशोधित अधिनियम और नए नियम और विनियम संबंधित ज्मवै प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले फेक्टरकी ओर से सीधे सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्वोरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्वोरिटी इंटेरेस्ट (CERSAI) के साथ चार्ज रजिस्टर करने की अनुमति देते हैं, जिससे प्रक्रिया को परिचालनात्मक रूप से कुशल बनाया जा सके, टीआरईडीएस के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके और फेक्टर पर प्रक्रियात्मक बोझ को कम किया जा सके।
- 'असाइनमेंट', 'फैक्ट्रिंग बिजनेस' और 'रिसीवेबल्स' की परिभाषाओं को अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुरूप लाने के लिए संशोधित किया गया है।
- धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण-पत्र देने की विधि, और धारा 19 के अंतर्गत फेक्टर की ओर से टीआरईडीएस संस्थाओं द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ लेनदेन के विवरण दाखिल करने की विधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को विनियमन बनाने की शक्तियां दी गई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन विनियमों को जनवरी 2022 में अधिसूचित किया है।

संशोधनों ने अधिनियम में प्रतिबंधात्मक उपबंधों को उदार बनाया है और साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत एक मजबूत नियामक/निगरानी तंत्र मौजूद रहे। कुल मिलाकर, इस परिवर्तन से देश में फेक्ट्रिंग पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार होगा और क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करके एमएसएमई को सारवान सहायता प्राप्त होगी।

## पूँजी बाजार में विकास

### 1. प्राथमिक बाजार

#### क. इक्विटी

4.36 अप्रैल-नवंबर 2021 में, 75 कंपनियों के आईपीओ को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे ₹ 89,066 करोड़ एकत्र किए गए, जबकि 29 कंपनियों ने अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान घ14,733 करोड़ जुटाए थे, जो निधि जुटाने/संग्रहण में 504.5 प्रतिशत की शानदार वृद्धि का संकेत देता है। आईपीओ द्वारा जुटाई गई राशि पिछले दशक में किसी भी वर्ष में बड़े अंतर से जुटाई गई राशि से अधिक रही है। राइट्स इश्यू के माध्यम से जुटाई गई राशि हालांकि अप्रैल-नवंबर 2021 में 62.6 प्रतिशत घटकर ₹ 22,659 करोड़ रह गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹ 60,608 करोड़ थी। हालांकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए जुटाई गई राशि में 52.9 फीसदी की गिरावट आई है। अधिमान्य आवंटन के माध्यम से जुटाई गई राशि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 67.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

<sup>3</sup> यह एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जो एमएसएमई द्वारा प्राप्तियों की पारदर्शी और ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देता है। ज्मवै में, विक्रेता को चुनने के लिए कई फाइनेंसर मिलते हैं, विभिन्न ब्याज दरों का विकल्प, और बिना किसी संपार्श्विक के विक्रेता को पारदर्शी तरीके से सर्वोत्तम सौदा प्राप्त करने में मदद करता है। सरकार ने टीआरईडीएस पर पंजीकरण के लिए बड़े कॉर्पोरेट्स/सीपीएसई द्वारा पंजीकरण को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं।



कुल मिलाकर, अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान इक्विटी इश्यू के जरिए ₹1.81 लाख करोड़ जुटाए गए हैं, ऐसा जनता में वितरण प्रस्ताव, राइट्स, क्यूआईपी और अधिमान्य इश्यू जैसे विविध तरीकों के माध्यम से किया गया (तालिका 7)।

**तालिका 7: सार्वजनिक और राइट्स इश्यू (इक्विटी) के माध्यम से प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना**

अवधि	सार्वजनिक (आईपीओ+ एफपीओ)		राइट्स		क्यूआईपी		अधिमान्य इश्यू		कुल	
	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)
2016-17	106	29,210	12	3,274	20	8,464	409	44,235	547	85,183
2017-18	189	78,497	23	21,268	54	71,033	420	59,527	686	2,30,325
2018-19	136	21,720	9	2,001	14	8,678	402	2,10,159	561	2,42,559
2019-20	62	21,382	17	55,667	14	54,389	284	1,74,886	377	3,06,325
2020-21	57	46,060	21	64,059	31	78,738	234	40,940	343	2,29,797
अप्रैल-नवंबर 2020	30	29,733	15	60,608	16	56,725	145	25,701	206	1,72,768
अप्रैल-नवंबर 2021	75	89,066	18	22,659	23	26,704	233	43,004	349	1,81,433

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

4.37 वर्ष 2021-22 अब तक प्राथमिक बाजारों के लिए एक असाधारण वर्ष रहा है, जिसमें कई नए युग की कंपनियों/तकनीकी स्टार्ट-अप्स/यूनिकॉर्न्स द्वारा आईपीओ के माध्यम से धन उगाहने में उछाल आया है। लिस्टिंग के साथ जुड़ा उत्साह खुदरा द्वारा भारी ओवरसब्सक्रिप्शन में प्रकट हुआ, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) और संस्थागत निवेशकों और शानदार लिस्टिंग लाभ ने अधिक से अधिक कंपनियों को बाजारों से लाभ उठाना करने के लिए प्रेरित किया है (तालिका 8)। नए जमाने की कंपनियों के आईपीओ में निवेशकों की सभी श्रेणियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया न केवल बाजारों में, बल्कि कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन और लंबे समय में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं में भी विश्वास को दर्शाती है।

**तालिका 8: आईपीओ ओवरसब्सक्रिप्शन प्रवृत्ति**

ओवरसब्सक्रिप्शन-रेंज (ओवरसब्सक्राइब की गयी बारियों की संख्या)	सूचीबद्ध आईपीओ की संख्या (अप्रैल-नवंबर 2021)
>100	8
≥51 ≤100	11
≥21 ≤ 50	6
≥ 11 ≤ 20	11
≥1 ≤ 10	39
< 1	Nil
<b>Total</b>	<b>75</b>

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई)

**ख. ऋण**

4.38 ऋण पक्ष में, अप्रैल-नवंबर 2021 में कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि लगभग ₹3.7 लाख करोड़ थी। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 20 पब्लिक इश्यू(सार्वजनिक निर्गमों) के जरिए ₹9,132 करोड़ जुटाए जाने से ऋण में पब्लिक इश्यू के जरिए जुटाई गई रकम दोगुनी हो गई, 10 पब्लिक इश्यू(सार्वजनिक निर्गमों) की तुलना में, जिन्होंने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹3,871 करोड़ जुटाए थे। हालाँकि, प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए मुद्दों की संख्या और राशि में गिरावट आई क्योंकि अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान 1,299 इश्यू के माध्यम से जुटाए गए ₹4.9 लाख करोड़ की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान 851 इश्यू के माध्यम से 3.6 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे, (तालिका 9)। कुल मिलाकर, कर्ज वसूली धीमी हो गई, यह इक्विटी बाजार के विपरीत सुझाव देती है जिससे अब निवेशक अधिकतम जोखिम लेने के लिए तैयार है।

**तालिका 9: कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में संसाधन जुटाना**

वर्ष	पब्लिक इश्यू		प्राइवेट प्लेसमेंट	
	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)	इश्यू की संख्या	राशि (₹ करोड़)
2016-17	14	29,093	3,377	6,40,716
2017-18	8	5,173	2,706	5,99,147
2018-19	25	36,679	2,358	6,10,318
2019-20	34	14,984	1,787	6,74,703
2020-21	18	10,588	1,995	7,71,840
अप्रैल-नवंबर 2020	10	3,871	1,299	4,88,071
अप्रैल-नवंबर 2021	20	9,132	851	3,62,458

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

4.39 इक्विटी और ऋण के अलावा, कॉर्पोरेट बड़ी संख्या में नए और लिखित जैसे कि हाइब्रिड और कन्वर्टिबल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) आदि में भी ला रहे हैं (तालिका 10)। इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा अप्रैल-नवंबर 2021 में ₹15,506 करोड़ के संसाधन जुटाए गए थे।

**तालिका 10: रियल एस्टेट निवेश न्यासों (REITs), अवसंरचना निवेश न्यासों (InvITs) द्वारा निधि जुटाना**

फंड जुटाने का तरीका	2019-20		2020-21		अप्रैल 2021-नवम्बर 2021	
	संख्या	राशि (₹ करोड़)	संख्या	राशि (₹ करोड़)	संख्या	राशि (₹ करोड़)
रियल एस्टेट निवेश न्यासों (REITs) द्वारा कुल निधि जुटाना	0	0	3	14,300	0	0
सूचीबद्ध REITs	0	0	3	14,300	0	0
अवसंरचना निवेश न्यासों (InvITs) द्वारा कुल निधि जुटाना	4	11,496	2	40,432	6	15,506

सूचीबद्ध InvITs	3	7,744	1	25,215	5	15,125
गैर-सूचीबद्ध InvITs	1	3,753	1	15,217	1	382

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

**बॉक्स 5: मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल ( MSCI ) उभरते बाजारों का सूचकांक और भारत का भारांक( भार-प्रतिशत )**

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का एक प्रमुख पहलू एमएससीआई(MSCI) जैसे वैश्विक सूचकांक हैं, जिसमें 16.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की इक्विटी परिसंपत्तियों का (30 जून, 2021 तक) बेंचमार्क सूचकांक तैयार किया गया है। सबसे लोकप्रिय एमएससीआई(MSCI) सूचकांकों में से एक एमएससीआई(MSCI) इमर्जिंग मार्केट(EM) सूचकांक है जो भारत सहित 25 देशों के उभरते बाजार में बड़ी और मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी निष्पादन को दर्शाते हैं। 2001 में शुरू किया गया, MSCI EM इंडेक्स आज उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 1420 सूचीबद्ध संस्थाओं को सम्मिलित करता है। कंपनियों को सूचकांक में शामिल किए जाने के लिए पूर्ण बाजार पूंजीकरण, फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण, स्टॉक तरलता और विदेशी समावेश फेक्टर से संबंधित कुछ न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना होता है। कई वैश्विक संस्थागत निवेशक बेंचमार्क सूचकांकों के अनुरूप पूंजी आवंटित करने के लिए अपनी निष्क्रिय निवेश रणनीति(Passive investment strategy) के हिस्से के रूप में एमएससीआई के ईएम सूचकांक और अन्य बाजारों और विषयों को सम्मिलित करने वाले ऐसे कई सूचकांकों का उपयोग करते हैं। एमएससीआई-ईएम(MSCI EM) सूचकांक में भारत का (भारांक)भार-प्रतिशत इसके इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPI) को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (चित्र 5क)।

जून 2017 में, एमएससीआई(MSCI) ने घोषणा की थी कि जून 2018 से चीन के A-शेयरों<sup>4</sup> को एमएससीआई-ईएम(MSCI EM) सूचकांक में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। इसका अभिप्राय अन्य सभी देशों के भार-प्रतिशत में धीरे-धीरे कमी होना था। परिणामतः, एमएससीआई-ईएम(MSCI EM) इंडेक्स में भारत का भारांक(भार-प्रतिशत) अगस्त 2018 में 9.32 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2020 में 8.3 प्रतिशत हो गया।

बाद में, सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 से भारतीय कंपनियों के लिए लागू प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्षेत्रीय सीमा(जो अब अधिक है) के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPI) सीमा में ढील दे दी है। परिणामतः, भारत की फॉरेन ओनरशिप लिमिटेड(FOL) अपने वैश्विक सूचकांकों में 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी हो गई। परिणामस्वरूप, एमएससीआई(MSCI) इंडिया का फॉरेन इनक्लूजन फैक्टर(FIF) 7 प्रतिशत बढ़कर 0.39 से 0.42 हो गया। तदनुसार, एमएससीआई-ईएम( MSCI EM) सूचकांक में भारत का भारांक 8 प्रतिशत से तुरंत बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गया। उल्लेखनीय रूप से, क्षेत्रीय सीमा तक एफपीआई सीमा में वृद्धि ने अन्य प्रमुख इक्विटी सूचकांकों में भी भारतीय प्रतिभूतियों के भारांक(भार-प्रतिशत) को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया है, जैसे कि MSCI APxJ (100 बीपीएस), MSCI AC विश्व-सूचकांक(16 बीपीएस)। दिसंबर 2021 तक, एमएससीआई-ईएम( MSCI EM) इंडेक्स में भारत का भारांक 12.45 प्रतिशत है और 2,379 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एयूएम-मूल्य (Assets Under Management&value) वाली 106 सूचीबद्ध भारतीय संस्थाएं एमएससीआई ईएम(MSCI EM) सूचकांक का भाग हैं (चित्र 5ख)।

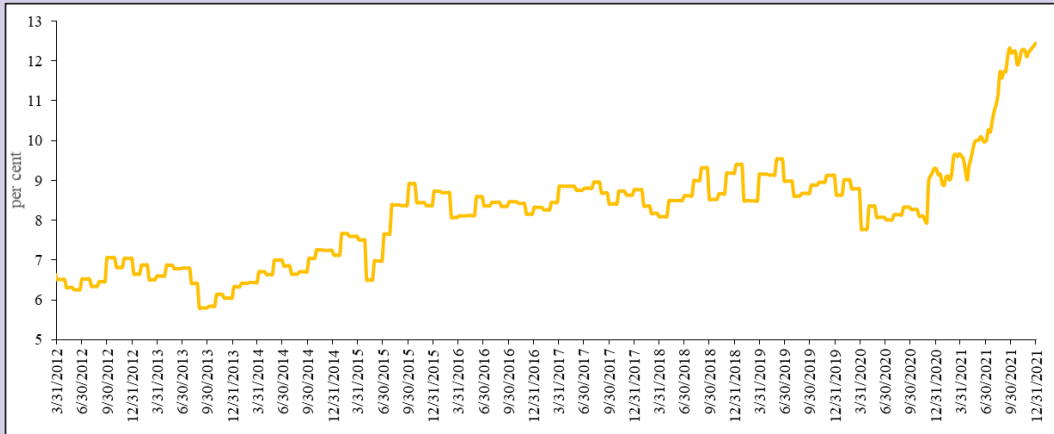
भारतीय पूंजी बाजारों में विदेशी रुचि बढ़ी है, जैसा कि बड़े निवेश प्रवाह से पता चलता है। नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड(NSDL)से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार,2020-21 में भारतीय इक्विटी बाजार में 2.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPI) प्रवाह देखा गया।

<sup>4</sup> A शेयर' सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध चीन की मुख्य भूमि कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज या शेनजेन स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करती हैं।

<sup>5</sup> किसी देश की सूचीबद्ध प्रतिभूति में विदेशी निवेशक किस सीमा तक निवेश कर सकते हैं। एफपीआई सीमा में वृद्धि, विदेशी निवेश के लिए उपलब्ध अवसर को बढ़ाती है।

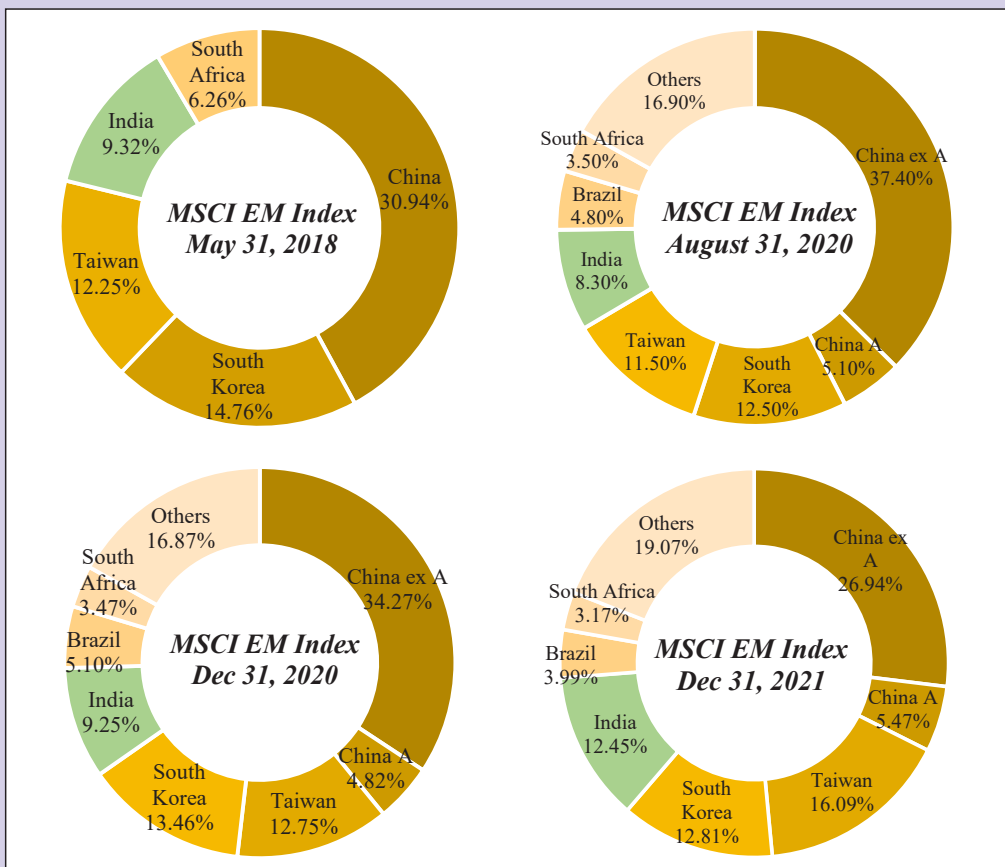
<sup>6</sup> एक प्रतिभूति सुरक्षा के फॉरेन इनक्लूजन फैक्टर को बकाया शेयरों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा सार्वजनिक इक्विटी बाजारों में खरीद के लिए उपलब्ध माना जाता है।

चित्रा 5 क: एमएससीआई ईएम (MSCI EM) सूचकांक पर भारत का भारांक( भार-प्रतिशत )



स्रोत: आरआईएमईएस,मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल ,मॉर्गन स्टेनली रिसर्च

चित्रा 5 ख: एमएससीआई ईएम (MSCI EM) सूचकांक की रचना: समय के साथ भारत का भारांक( भार-प्रतिशत ) कैसे बदल गया है



स्रोत: आरआईएमईएस,मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल ,मॉर्गन स्टेनली रिसर्च

## पूंजी बाजार में खुदरा भागीदारी में प्रवृत्ति

4.40 भारतीय शेयर बाजारों में लगातार उत्साह(तेजी के) के साथ, इक्विटी कैश सेगमेंट में व्यक्तिगत निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है और एनएसई पर कुल कारोबार में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी 2019-20 में 38.8 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर 2021 में 44.7 प्रतिशत हो गई है (तालिका 11)। 2020-21 और 2021-22 में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि के लिए आंशिक रूप से, फरवरी 2020 से देखे गए, नए निवेशक पंजीकरण में वृद्धि को श्रेय दिया जा सकता है। अप्रैल-नवंबर 2021 में लगभग 221 लाख व्यक्तिगत डीमैट खाते जोड़े गए।

**तालिका 11: इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर(एनएसई) में व्यक्तिगत निवेशकों का हिस्सा (प्रतिशत में)**

वर्ष	व्यक्तिगत निवेशकों का हिस्सा
2016-17	36.0
2017-18	39.0
2018-19	39.0
2019-20	38.8
2020-21	45.0
अप्रैल-अक्टूबर 2021	44.7

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

## 2. म्यूचुअल फंड गतिविधियां

4.41 म्यूचुअल फंड उद्योग का शुद्ध एयूएम मूल्य (AUM) नवंबर 2021 के अंत में 24.4 प्रतिशत बढ़ गया, जो नवंबर 2020 के अंत में ₹ 30.0 लाख करोड़ थी, अब बढ़ कर ₹ 37.3 लाख करोड़ हो गई। अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान ₹ 2.73 लाख करोड़ की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान म्यूचुअल फंड द्वारा ₹ 2.54 लाख करोड़ का शुद्ध संसाधन जुटाया गया (तालिका 12)।

**तालिका 12: म्यूचुअल फंड के माध्यम से संसाधन जुटाना**

वर्ष	एयूएम (₹ करोड़)	सकल संसाधन जुटाना (₹ करोड़)	सकल मोचन (₹ करोड़)	शुद्ध संसाधन जुटाना (₹ करोड़)	फोलियो की संख्या
2016-17	17,54,619	1,76,15,549	1,72,72,500	3,43,049	5,53,99,631
2017-18	21,36,036	2,09,98,652	2,07,26,855	2,71,797	7,13,47,301
2018-19	23,79,663	2,43,94,362	2,42,84,661	1,09,701	8,24,56,411
2019-20	22,26,203	1,88,13,458	1,87,26,157	87,301	8,97,46,051
2020-21	31,42,764	86,39,167	84,24,424	2,14,743	9,78,65,529
अप्रैल-नवम्बर 2020	30,00,904	57,90,831	55,17,814	2,73,017	9,36,79,333
अप्रैल-नवम्बर 2021	37,33,702	58,64,573	56,10,534	2,54,039	11,69,91,489

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

<sup>7</sup> व्यक्तिगत निवेशकों में व्यक्तिगत घरेलू निवेशक, एनआरआई, एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म और एचयूएफ, अन्य: साझेदारी फर्म/एलएलपी, ट्रस्ट/सोसाइटी, डिपॉजिटरी रसीदें, वैधानिक निकाय, ओसीबी, एफएन, आदि शामिल हैं।

## विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( FPI ) द्वारा निवेश

4.42 अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( FPI ) ने भारतीय प्रतिभूतियों में ₹ 24,124 करोड़ का शुद्ध निवेश किया, जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में किए गए निवेश की तुलना में 82.8 प्रतिशत कम था। नवंबर 2020 के अंत में एफपीआई ( FPI ) द्वारा संचयी शुद्ध निवेश 264 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 9.2 प्रतिशत बढ़कर नवंबर 2021 तक 288.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (तालिका 13)।

तालिका 13: भारतीय प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश

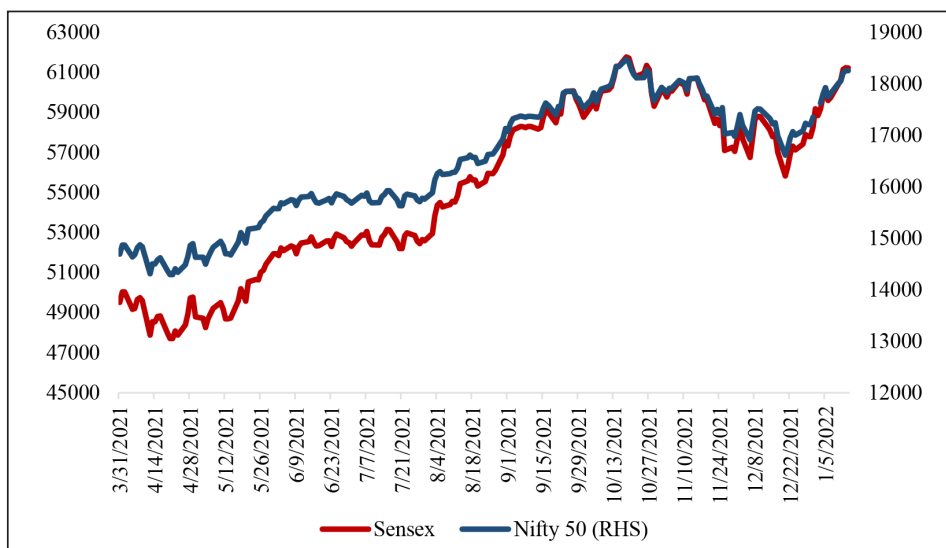
वर्ष /माह	सकल खरीद (₹ करोड़)	सकल बिक्री (₹ करोड़)	शुद्ध निवेश (₹ करोड़)	शुद्ध निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	संचयी शुद्ध निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
2016-17	15,07,028	14,58,617	48,411	7,600	2,31,180
2017-18	17,28,360	15,83,679	1,44,681	22,466	2,53,645
2018-19	16,40,810	16,79,741	-38,931	-5,499	2,48,147
2019-20	19,05,517	19,33,046	-27,529	-3,042	2,45,105
2020-21	23,20,289	20,53,189	2,67,100	36,180	2,81,293
अप्रैल-नवम्बर 2020	13,75,673	12,35,286	1,40,387	18,896	2,64,008
अप्रैल-नवम्बर 2021	16,23,155	15,99,030	24,124	3,371	2,88,364

स्रोत: नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड(NSDL)

## भारतीय बेंचमार्क सूचकांक

4.43 भारत में बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक - सेंसेक्स और निफ्टी 50 में अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान क्रमशः 17.7 प्रतिशत और 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छी कॉर्पोरेट आय होने, कोविड -19 टीकाकरण में तेज वृद्धि और देश भर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खोले जाने से 18 अक्टूबर 2021 को सेंसेक्स और निफ्टी सूचकांक क्रमशः 61,766 और 18,477 पर अपने चरम पर पहुंच गए (चित्र 18) । उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी बेंचमार्क सूचकांक में गिरावट हुई, तथापि इनका फिर से बढ़ना शुरू हो गया और 14 जनवरी 2022 को क्रमशः 61,223 और 18,256 पर पहुँच गए हो।

चित्र 18: भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों की चाल



स्रोत: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संवेदनशील सूचकांक (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)

4.44 प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय बाजारों ने अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया। चुनिंदा विकसित बाजारों में, एसएंडपी 500 इंडेक्स और नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स ने मजबूत लाभ दर्ज किया और इनमें क्रमशः 20.0 प्रतिशत और 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 14)।

तालिका 14: दुनिया भर में 2021-22 में प्रमुख शेयर बाजार सूचकांकों का निष्पादन

सूचकांक	31/03/2021 तक	31/12/2021 तक	अप्रैल-दिसंबर 2020 में % परिवर्तन	अप्रैल-दिसंबर 2021 में % परिवर्तन
<b>भारतीय बाजार</b>				
निफ्टी 50	14,691	17,354	62.6	<b>18.1</b>
एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स	49,509	58,254	62.0	<b>17.7</b>
<b>उभरते बाजार</b>				
ताइवान TAIEX	16,431	18,219	51.8	10.9
एफटीएसई/जेएसई ऑल शेयर इंडेक्स, दक्षिण अफ्रीका	66,485	73,709	33.5	10.9
MOEX रूस सूचकांक	3,542	3,787	31.1	6.9
शंघाई कम्पोजिट, चीन	3,442	3,640	26.3	5.7
कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स KOSPI दक्षिण कोरिया	3,061	2,978	63.8	-2.7
ब्राजील Ibovespa	1,16,634	1,04,822	63.0	-10.1
<b>विकसित बाजार</b>				
एस एंड पी 500, यूएस	3,973	4,766	45.3	20.0
नैस्डैक कम्पोजिट, यूएस	13,247	15,645	67.4	18.1

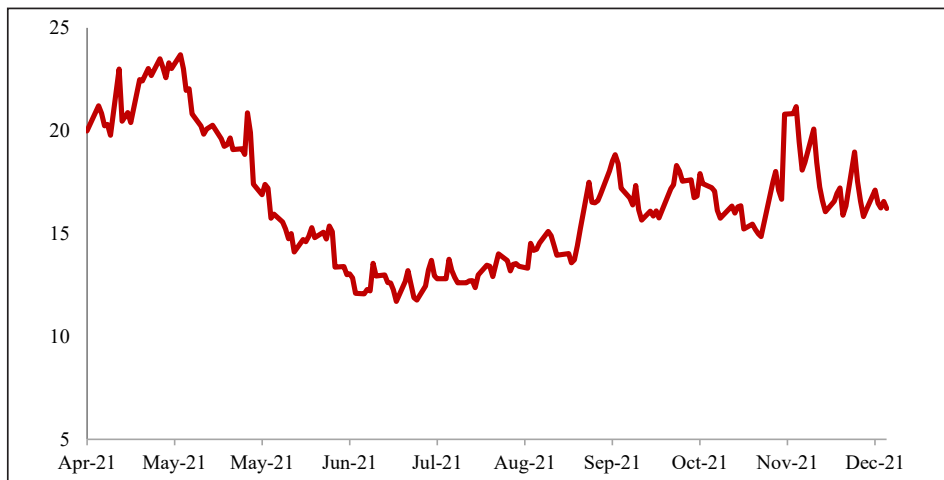


सीएसी 40, फ्रांस	6,067	7,153	26.3	17.9
डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, यूएस	32,982	36,338	39.6	10.2
एफटीएसई 100, यूके	6,714	7,385	13.9	10.0
डैक्स, जर्मनी	15,008	15,885	38.1	5.8
स्ट्रेट्स टाइम्स, सिंगापुर	3,165	3,124	14.6	-1.3
Nikkei 225, जापान	29,179	28,792	45.1	-1.3
हैंग सेंग, हांगकांग	28,378	23,398	15.4	-17.6

स्रोत: रिफाइनिटिव डेटास्ट्रीम

4.45 अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, भारतीय वॉलेटिलिटी इंडेक्स (विक्स) (India VIX), जो निकट भविष्य में अर्थात अगले 30 कैलेंडर दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावनाओं को दर्शाता है, 3 मई 2021 को 23.7 पर पहुंच गया और बाद में कम होना शुरू हो गया घ इसमें कुछ समय के लिए तेजी आई और नवंबर 2021 में यह फिर से कम हो गया। कुल मिलाकर, अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान टप में 21.4 प्रतिशत की कमी हुई।

चित्र 19: भारतीय वॉलेटिलिटी इंडेक्स ( भारतीय विक्स ) ( India VIX )



स्रोत: एनएसई

## बीमा क्षेत्र

4.46 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बीमा क्षेत्र की क्षमता और निष्पादन का आकलन आम तौर पर दो मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जैसे बीमा-व्यापन (insurance penetration) और बीमा-घनत्व (insurance density)। बीमा-व्यापन (insurance penetration) को सकल घरेलू उत्पाद में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है और बीमा-घनत्व (insurance density) की गणना, बीमा-प्रीमियम के जनसंख्या के अनुपात के रूप में की जाती है (अंतराष्ट्रीय तुलना की सुविधा के लिए यूएस डॉलर्स में इनका मापान किया जाता है)।

4.47 भारत में, 2001 में बीमा-व्यापन (insurance penetration) 2.71 प्रतिशत था और लगातार बढ़कर 2020 में यह 4.2 प्रतिशत हो गया है। 2020 तक, भारत में जीवन बीमा-व्यापन 3.2 प्रतिशत है और गैर-जीवन बीमा-व्यापन 1 प्रतिशत है (तालिका 15 और 16) घ यद्यपि भारत में 'जीवन बीमा' के लिए

बीमा-व्यापन(insurance penetration) अंतरराष्ट्रीय औसत के बराबर है, किंतु हम गैर-जीवन बीमा के क्षेत्र में अभी पीछे हैं। विश्व स्तर पर, 2020 में जीवन बीमा वर्ग के लिए बीमा-व्यापन(insurance penetration) 3.3 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा वर्ग के लिए 4.1 प्रतिशत था।

**तालिका 15: भारत में जीवन बीमा का व्यापन( penetration ) और घनत्व( density )**

विवरण	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
बीमा-व्यापन	3.40	3.17	3.10	2.60	2.72	2.72	2.76	2.74	2.82	3.20
बीमा-घनत्व	49.0	42.7	41.0	44.0	43.2	46.5	55.0	55.0	58.0	59.0

स्रोत: स्विस री इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड, सिग्मा विभिन्न इश्यू

नोट: बीमा व्यापन (penetration) प्रतिशत में और बीमा घनत्व (density) अमेरिकी डॉलरों में है

**तालिका 16: भारत में गैर-जीवन बीमा का व्यापन ( penetration ) और घनत्व ( density )**

विवरण	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
बीमा-व्यापन	0.70	0.78	0.80	0.70	0.72	0.77	0.93	0.97	0.94	1.00
बीमा-घनत्व	10.0	10.5	11.0	11.0	12.0	13.2	18.0	19.0	20.0	19.0

स्रोत: स्विस री इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड, सिग्मा विभिन्न इश्यू

नोट: बीमा-व्यापन (penetration) प्रतिशत में और बीमा-घनत्व (density) अमेरिकी डॉलरों में है

4.48 भारत में बीमा घनत्व 2001 में +11.5 (अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर 2020 में +78 (अमेरिकी डॉलर) हो गया। 2020 में, भारत में जीवन बीमा के लिए बीमा-घनत्व (density) +59 है और गैर-जीवन बीमा के लिए बीमा-घनत्व (density) +19 है, जो वैश्विक मानकों से बहुत कम है। वैश्विक स्तर पर, 2020 में जीवन वर्ग के लिए बीमा-घनत्व (insurance density) क्रमशः +360 और गैर-जीवन वर्ग के लिए +449 था (तालिका 17 और 18)।

**तालिका 17: बीमा-व्यापन ( penetration ) की अंतराष्ट्रीय तुलना ( प्रतिशत में )**

क्रम संख्या	देश*	2019			2020		
		जीवन-बीमा	गैरजीवन-बीमा	कुल	जीवन-बीमा	गैरजीवन-बीमा	कुल
अमेरिका							
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	2.9	8.5	11.4	3.0	9.0	12.0
2	कनाडा	3.1	4.6	7.7	3.5	5.2	8.7
3	ब्राजिल	2.3	1.8	4.0	2.3	1.8	4.1
4	मेक्सिको	1.1	1.3	2.4	1.2	1.4	2.6
यूरोप - मध्य पूर्वी देश - अफ्रीका							
5	फ्रांस	6.0	3.2	9.2	5.1	3.5	8.6
6	जर्मनी	2.6	3.7	6.3	2.8	4.0	6.8
7	इटली	6.2	2.2	8.3	6.3	2.3	8.6
8	नीदरलैंड	1.6	7.6	9.2	1.5	8.1	9.6
9	स्पेन	2.2	2.9	5.1	1.9	3.2	5.2

10	स्वीडन	5.4	1.8	7.2	5.8	1.8	7.6
11	स्विट्जरलैंड	4.3	4.1	8.4	4.3	4.1	8.4
12	यूनाइटेड किंगडम	8.0	2.3	10.3	8.8	2.3	11.1
13	पाकिस्तान	0.6	0.3	0.9	0.5	0.3	0.8
14	रूस	0.4	1.0	1.4	0.4	1.0	1.4
15	दक्षिण अफ्रीका	10.7	2.7	13.4	11.2	2.5	13.7
<b>एशिया प्रशांत</b>							
16	भारत <sup>#</sup>	<b>2.8</b>	<b>0.9</b>	<b>3.8</b>	<b>3.2</b>	<b>1.0</b>	<b>4.2</b>
17	चीन	2.3	2.0	4.3	2.4	2.1	4.5
18	जापान <sup>#</sup>	6.7	2.3	9.0	5.8	2.4	8.1
19	इंडोनेशिया	1.4	0.6	2.0	1.4	0.5	1.9
20	मलेशिया <sup>#</sup>	3.4	1.4	4.7	4.0	1.5	5.4
21	सिंगापुर	6.0	1.6	7.6	7.6	1.9	9.5
22	दक्षिण कोरिया <sup>#</sup>	5.8	5.0	10.8	6.4	5.2	11.6
23	ताइवान	16.5	3.5	20.0	14.0	3.4	17.4
24	थाईलैंड	3.3	1.7	5.0	3.4	1.9	5.3
25	श्रीलंका	0.6	0.7	1.3	0.5	0.6	1.2
26	न्यूजीलैंड	0.9	4.3	5.1	0.8	4.1	4.9
27	ऑस्ट्रेलिया	1.5	3.4	5.0	1.1	3.6	4.7
	<b>विश्व</b>	<b>3.4</b>	<b>3.9</b>	<b>7.2</b>	<b>3.3</b>	<b>4.1</b>	<b>7.4</b>

स्रोत: स्विस री इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड सिग्मा वॉल्यूम 4/2020 और 3/2021

नोट: \*डेटा कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 से संबंधित है, # डेटा वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित है @ पूर्णांकित अंतर

**तालिका 18: बीमा-घनत्व ( insurance density ) की अंतर्राष्ट्रीय तुलना ( अमेरिकी डॉलर में )**

क्रम संख्या	देश*	2019			2020		
		जीवन-बीमा	गैरजीवन-बीमा	कुल	जीवन-बीमा	गैरजीवन-बीमा	कुल
<b>अमेरिका</b>							
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	1,915	5,580	7,495	1,918	5,754	7,673
2	कनाडा	1,421	2,128	3,548	1,532	2,243	3,775
3	ब्राजिल	196	155	351	151	120	271
4	मेक्सिको	111	128	239	99	116	214
<b>यूरोप - मध्य पूर्वी देश - अफ्रीका</b>							
5	फ्रांस	2,413	1,306	3,719	1,959	1,359	3,317
6	जर्मनी	1,222	1,712	2,934	1,281	1,827	3,108
7	इटली	2,039	725	2,764	1,972	721	2,692
8	नीदरलैंड	832	3,990	4,822	799	4,223	5,022

9	स्पेन	654	854	1,508	525	871	1,396
10	स्वीडन	2,783	946	3,729	2,993	945	3,938
11	स्विट्जरलैंड	3,502	3,332	6,835	3,667	3,557	7,224
12	यूनाइटेड किंगडम	3,383	978	4,362	3,574	949	4,523
13	पाकिस्तान	8	4	12	6	3	10
14	रूस	43	113	157	41	105	146
15	दक्षिण अफ्रीका	643	160	803	560	124	684
<b>एशिया प्रशांत</b>							
16	भारत <sup>#</sup>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>78<sup>@</sup></b>	<b>59</b>	<b>19</b>	<b>78</b>
17	चीन	230	201	430	241	214	455
18	जापान <sup>#</sup>	2,691	930	3,621	2,329	951	3,280
19	इंडोनेशिया	58	24	82	54	21	75
20	मलेशिया <sup>#</sup>	380	156	536	415	153	568
21	सिंगापुर	3,844	1,028	4,872	4,528	1,110	5,638
22	दक्षिण कोरिया <sup>#</sup>	1,822	1,544	3,366	2,050	1,691	3,741
23	ताइवान	4,129	865	4,993	3,861	938	4,800
24	थाईलैंड	256	134	389	244	139	383
25	श्रीलंका	23	29	51	21	24	45
26	न्यूजीलैंड	354	1,790	2,144	349	1,678	2,027
27	ऑस्ट्रेलिया	827	1,875	2,702	568	1,880	2,448
<b>विश्व</b>		<b>379</b>	<b>439</b>	<b>818</b>	<b>360</b>	<b>449</b>	<b>809</b>

स्रोत: स्विस रि इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड सिग्मा वॉल्यूम 4/2020 और 4/2021

नोट: \*डेटा कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 से संबंधित है, # डेटा वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित है@पूर्णकित अंतर

4.49 2019-20 में ₹ 1,92,193 करोड़ की तुलना में 2020-21 के दौरान, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के भीतर और बाहर) ₹ 2,02,082 करोड़ था इसमें 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। मोटर और स्वास्थ्य वर्ग ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया छ जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्त वर्ष के ₹ 5,72,910 करोड़ की तुलना में, 2020-21 के दौरान ₹ 6,28,731 करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की, इसमें 9.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा दिया गया नवीकरण प्रीमियम प्राप्त कुल प्रीमियम का 55.7 प्रतिशत था, शेष 44.3 प्रतिशत प्रीमियम नए ग्राहकों के बीमे से प्राप्त हुआ।

## पेंशन क्षेत्र

4.50 नई पेंशन योजना (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत ग्राहकों की कुल संख्या सितंबर 2020 तक 374.32 लाख से बढ़कर सितंबर 2021 तक 463 लाख हो गई, इसमें वर्ष के दौरान 23.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान नई पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत कुल अंशदान में 29 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। अधिकतम वृद्धि आल सिटीजन मॉडल (51.29 प्रतिशत) के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र (42.13 प्रतिशत), एपीवाई (38.78 प्रतिशत), राज्य सरकार क्षेत्र, (28.90 प्रतिशत), और केंद्र सरकार क्षेत्र (22.04 प्रतिशत) द्वारा दर्ज की गई। एनपीएस और एपीवाई की एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 30 सितंबर, 2021 को 6.67 लाख करोड़ रुपये है, जबकि सितंबर, 2020 के अंत में यह 4.95 लाख करोड़ रुपये थी, इस प्रकार 34.8 प्रतिशत की समग्र वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की गई (तालिका 19)।

तालिका 19: 30 सितंबर 2021 को नई पेंशन योजना (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) की स्थिति

	सब्सक्राइबर्स की संख्या (लाख में)		(वर्ष- दर- वर्ष)	अंशदान (₹ करोड़)		(वर्ष- दर- वर्ष)	एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM)		(वर्ष- दर- वर्ष)
	सितंबर-20	सितंबर-21	%	सितंबर-20	सितंबर-21	%	सितंबर-20	सितंबर-21	%
<b>NPS</b>									
केंद्र सरकार	21.3	22.3	4.5	1,11,293	1,35,820	22.0	1,60,606	2,04,227	27.2
राज्य सरकार	49.0	53.9	10.1	1,88,000	2,42,330	28.9	2,50,260	3,35,749	34.2
कॉर्पोरेट	10.5	12.7	21.0	37,788	53,707	42.1	50,730	77,041	51.9
आल सिटीजन मॉडल	13.6	18.4	35.3	17,282	26,145	51.3	16,224	27,089	67.0
एनपीएस लाइट	43.2	42.9	-0.7	2,776	2,931	5.6	4,068	4,624	13.7
<b>अटल पेंशन योजना (APY)</b>									
अटल पेंशन योजना	236.9	312.9	32.1	11,585	16,078	38.8	13,042	18,649	43.0
<b>Total</b>	<b>374.3</b>	<b>463</b>	<b>23.7</b>	<b>3,68,725</b>	<b>4,77,011</b>	<b>29.4</b>	<b>4,94,930</b>	<b>6,67,379</b>	<b>34.8</b>

स्रोत : पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

नोट: UOS-All citizen model - अटल पेंशन योजना।

4.51 12 अक्टूबर 2021 तक, 3.45 करोड़ से अधिक नामांकनों से अटल पेंशन योजना (APY) योजना में ₹16,109 करोड़ का अंशदान एकत्र किया गया था। अटल पेंशन योजना (APY) सभी बैंकों और डाकघरों सहित 250 से अधिक सक्रिय अटल पेंशन योजना (APY) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वितरित की जा रही है (तालिका 20)।

**तालिका 20: अटल पेंशन योजना ( APY ) के अंतर्गत नामांकनों की संख्या ( श्रेणी-वार )**

बैंकों की श्रेणी	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	12 <sup>th</sup> अक्टूबर 2021
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3,047,273	6,553,397	10,719,758	1,56,75,442	2,12,52,435	2,43,90,974
निजी बैंक	497,323	873,901	1,145,289	15,62,997	19,86,467	21,21,377
लघु वित्त बैंक	-	-	9,190	15,760	35,114	56,012
पेमेंट बैंक	-	-	48,182	3,44,001	8,18,800	10,93,602
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,115,257	1,987,176	3,171,152	43,30,190	57,10,770	64,15,150
जिला सहकारी बैंक	29,791	33,880	38,863	48,581	54,628	58,775
राज्य सहकारी बैंक	680	805	1,053	4,620	5,350	5,604
शहरी सहकारी बैंक	3,507	10,936	14,469	17,355	20,095	21,881
डाक विभाग	189,998	245,366	270,329	3,02,712	3,32,141	3,44,132
<b>कुल</b>	<b>48,83,829</b>	<b>97,05,461</b>	<b>1,54,18,285</b>	<b>2,23,01,658</b>	<b>3,02,15,800</b>	<b>3,45,07,507</b>

स्रोत: पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

4.52 अटल पेंशन योजना (APY) में ग्राहकों की आयु प्रोफाइल से पता चलता है कि कम आयु के ग्राहक नामांकन के मामले बढ़ रहे हैं। मार्च 2016 को 29 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2021 तक 43 प्रतिशत से अधिक ग्राहक 18 से 25 वर्ष के बीच की आयु के थे य इसका अलावा, अधिक लोग अब ₹ 1000 प्रति माह की पेंशन राशि का विकल्प चुन रहे हैं। मार्च 2016 तक 38 प्रतिशत ग्राहकों की तुलना में, सितंबर 2021 तक, लगभग 78 प्रतिशत ग्राहकों ने ₹ 1000 प्रति माह पेंशन राशि का विकल्प चुना है। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2021 तक ₹ 2000/₹ 3000/₹ 4000 प्रति माह पेंशन का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है, जबकि 14 प्रतिशत ने ₹ 5000 प्रति माह पेंशन का विकल्प चुना।

4.53 अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत नामांकन में लैंगिक अंतर महिला ग्राहकों की बढ़ती भागीदारी के साथ कम हुआ है, महिला ग्राहकों की भागीदारी मार्च 2016 में 37 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 तक 44 प्रतिशत हो गई है। नीचे दी गई तालिका-21 में उन राज्यों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनके पास अटल पेंशन योजना (APY) खाता नामांकन 10 लाख या उससे अधिक है।

**तालिका 21: अटल पेंशन योजना ( APY ) खातों की संख्या ( 12 अक्टूबर 2021 तक )**

संख्या नं०	राज्य	ए पी वाई खातों की संख्या (लाख में)
1	उत्तर प्रदेश	51.9
2	बिहार	32.7
3	पश्चिम बंगाल	27.6

4	महाराष्ट्र	26.8
5	तमिलनाडु	25.5
6	आंध्र प्रदेश	20.5
7	कर्नाटक	20.5
8	मध्य प्रदेश	20.2
9	राजस्थान	17.2
10	गुजरात	14.3
11	ओडिशा	13.1

स्रोत: पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

4.54 पेंशन फंड में विदेशी कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों की कुल शेयर पूंजी(एग्रीगेट होल्डिंग) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में, सभी एनपीएस ग्राहकों के लिए वार्षिकीकरण (पूर्ण एकमुश्त) की आवश्यकता के बिना एनपीएस से बाहर निकलने की अनुमति की सीमा में उर्ध्वगामी संशोधन किया गया था, ग्राहक की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के मामले में ₹ 2 लाख से ₹ 5 लाख तक, साथ ही एनपीएस से समय से पहले निकलने के मामले में ₹ 1 लाख से ₹ 2.5 लाख तक। 60 वर्ष की आयु के बाद शामिल होने वाले ग्राहक 75 वर्ष की आयु तक, जो पहले 70 वर्ष थी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेशक/सब्सक्राइबर बने रह सकते हैं। अपने कर्मचारियों को पर्याप्त पेंशन मूल निधि संचय करने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सरकारी सह-अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। इसका विस्तार बैंक कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CABs) के लिए किया गया है। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान डिफॉल्ट रूप में लागू होने वाली योजना के अतिरिक्त किसी अन्य पेंशन फंड को चुनने के साथ-साथ अपने निवेश के स्वरूप को बदलने का विकल्प भी प्रदान किया है।

### दिवाला और शोधन-अक्षमता

4.55 दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (IBC) ने एक समेकित और व्यापक दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (IBC) के अधिनियमन के साथ, भारत ने दो व्यवसायों का जन्म देखा है, अर्थात् 'दिवाला व्यवसाय' और 'मूल्यांकन व्यवसाय, जिन्होंने दिवाला सेवाओं को व्यावसायिक बनाया है। संहिता ने समाधान की संभावनाओं को खोल दिया है, जिसमें विलय, समामेलन और किसी भी प्रकार का पुनर्गठन शामिल है, जिसके लिए प्रायः व्यावसायिकों की सहायता की आवश्यकता होती है। इसने दिवाला व्यावसायिकों, पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं, दिवाला व्यावसायिकों संस्थाओं की सेवाओं के लिए बाजार तैयार किया है और अधिवक्ताओं, लेखाकारों और अन्य पेशेवरों की सेवाओं के दायरे का विस्तार किया है (तालिका 22)।

तालिका 22: संहिता के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र

अपील-प्राधिकारी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की दो न्यायपीठ (बेंच)					
न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की 15 न्यायपीठ (बेंच)					
रेगुलेटर	भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड					
सेवा प्रदाता	As on					
	मार्च2017	मार्च2018	मार्च2019	मार्च2020	मार्च2021	सितम्बर 2021
इनफॉर्मेशन यूटिलिटी नेटवर्क	00	01	01	01	01	01



दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां	03	03	03	03	03	03
दिवाला व्यावसायिक	977* + 96	1812	2456	3004	3504	3816
दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं	03	75	48	69	83	86
पंजीकृत मूल्यांकक संगठन	NA	NA	11	12	16	16
पंजीकृत मूल्यांकक	NA	NA	1186	3030	3967	4366
पंजीकृत मूल्यांकक संस्थाएं	NA	NA	0	20	40	52

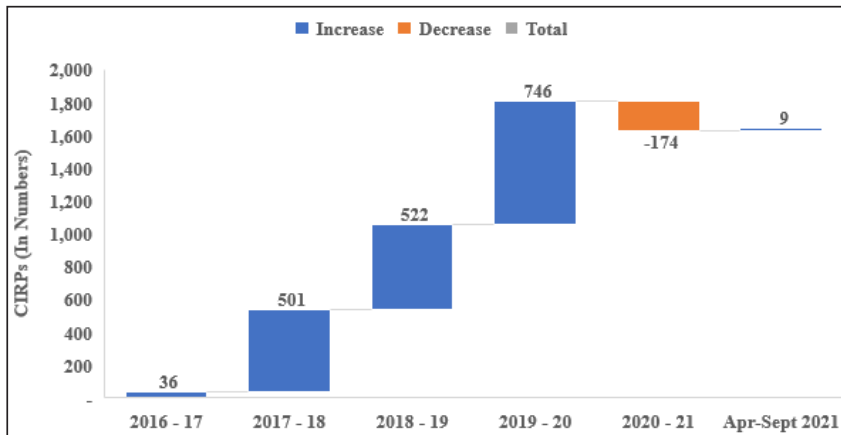
स्रोत: भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड

नोट: \*इन पंजीकरणों की वैधता छह महीने थी और यह 30 जून 2017 तक समाप्त हो गई थी

### संहिता के अंतर्गत परिणाम

4.56 कोविड-19 महामारी को देखते हुए दिवाला और शोधन-अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 5 जून 2020 को प्रख्यापित किया गया था, जिसने 25 मार्च 2020 को या उसके बाद होने वाले किसी भी डिफॉल्ट के लिए एक कॉर्पोरेट देनदार (CD) के कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) की शुरुआत को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा, महामारी के कारण तनाव से गुजर रही फर्मों को सहायता देने के लिए कोड के निलंबन को 24 सितंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 को प्रत्येक 3 महीने के लिए दो बार बढ़ाया गया था। निरंतर समाधानों के साथ संयुक्त छूट के कारण 2020-21 के दौरान मामलों की संख्या में गिरावट हुई है, यह सितंबर 2021 तक थोड़ी बढ़कर 1640 हो गयी है (चित्र 20)।

चित्र 20: सीआईआरपी संचय (30 सितंबर, 2021 तक)



स्रोत: एनसीएलटी की वेबसाइट से संकलन और आईपी द्वारा फाइलिंग।

नोट: ये सीआईआरपी 4,593 कॉर्पोरेट देनदारों (सीडी) के संबंध में हैं, इसमें 1 सीडी शामिल नहीं है जो सीधे बीआईएफआर से संकल्प में स्थानांतरित हो गई है, इसमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड डेटा शामिल है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर आवेदन को कोड के वित्तीय सेवा प्रदाता (एफएसपी) नियमों के साथ पढ़े गए धारा 227 के तहत स्वीकार किया गया था।

### (क) संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का बचाव

4.57 संहिता का प्राथमिक उद्देश्य संकट में फंसे कॉर्पोरेट देनदारों (सीडी) का समाधान करना है। सितंबर 2021 तक, कोड ने 421 सीडी को समाधान योजनाओं के माध्यम से बचाया और 1419 सीडी को परिसमापन के लिए भेज दिया। जब उन्हें कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में सम्मिलित/दाखिल किया गया

था तब बचाई गई सीडी में ₹ 1.48 लाख करोड़ की संपत्ति थी, जबकि परिसमापन के लिए संदर्भित सीडी में ₹ 0.52 लाख करोड़ की संपत्ति थी। यहां लगभग 74 प्रतिशत संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को बचाया गया था। परिसमापन के लिए भेजी गई सीडी में से तीन-चौथाई या तो बीमार थीं या निष्क्रिय थीं और बचाई गई फर्मों में से एक तिहाई या तो बीमार थीं या निष्क्रिय थीं। कुल सम्मिलित/दाखिल मामलों में से लगभग 65 प्रतिशत मामलों को या तो समाधान, निकासी या परिसमापन द्वारा बंद किया जा चुका है। चल रहे 1640 सीआईआरपी में से, लगभग 75 प्रतिशत मामले 270 दिनों से अधिक समय से जारी हैं (तालिका 23)।

**तालिका 23: 30 सितंबर, 2021 तक सीआईआरपी की स्थिति**

सीआईआरपी की स्थिति	सीआईआरपी की संख्या
सम्मिलित/दाखिल	4708
अपील / समीक्षा / निपटारे पर बंद	701
धारा 121 के अंतर्गत निकासी द्वारा बंद	527
समाधान द्वारा बंद	421
परिसमापन द्वारा बंद	1419
चल रहे/जारी सीआईआरपी	1640
> 270 days	1201
> 180 days ≤ 270 days	186
> 90 days ≤ 180 days	120
≤ 90 days	133

भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड

4.58 सीआईआरपी में प्रवेश करने पर बचाई गई 421 सीडी के पास उपलब्ध संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य केवल 1.48 लाख करोड़ रूपए था, हालांकि उन पर लेनदारों का 7.94 लाख करोड़ रूपए बकाया था। संकल्प योजनाओं से 2.55 लाख करोड़ रूपए की वसूली हुई, जो इन सीडी के वसूली योग्य मूल्य के 172 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि वसूली संहिता के तहत आकस्मिक है, वित्तीय लेनदारों (एफसी) ने अपने दावों का 32.11 प्रतिशत वसूल किया, जो सीडी के सीआईआरपी में प्रवेश करने के समय तक मूल्य क्षरण की सीमा को दर्शाता है, फिर भी यह वसूली के लिए लेनदारों के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों में सबसे अधिक है (तालिका 24)।

**तालिका 24: 30 सितंबर, 2021 तक संकटग्रस्त संपत्तियों की स्थिति ( राशि करोड़ रुपये में )**

विवरण	जिन कंपनियों को बचाया गया	जिन कंपनियों के परिसमापन का आदेश दिया गया	कुल
कंपनियों की संख्या	421	1419	1840
कुल दावे	794168	738631	1532799
परिसमापन मूल्य	147886	52036	199922
कुल दावों के प्रतिशत में उपलब्ध संपत्ति	18.62	7.04	13.04
समाधान मूल्य	254983	NA	254983
परिसमापन मूल्य के % के रूप में समाधान मूल्य	172.42	NA	NA
कुल दावों के % के रूप में समाधान मूल्य	32.11	NA	NA

लगने वाला औसत समय	495 days	375 days	435 days
समाधान मूल्य का लागत प्रतिशत	0.54	NA	NA

स्रोत: आई बी बी आई

### (ख) परिसमापन

4.59 परिसमापन के आदेशों के साथ समाप्त होने वाली 1419 सीडी पर कुल 7.38 लाख करोड़ रूपए का दावा था। हालांकि, उनके पास वास्तव में केवल 0.52 लाख करोड़ रूपए की संपत्ति थी। सितंबर 2021 तक, 264 सीडी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, जिन पर 45790 करोड़ रूपए के बकाया दावे थे, लेकिन संपत्ति का मूल्य 2025 करोड़ रूपए था। इन कंपनियों के परिसमापन के माध्यम से 1983 करोड़ रूपए की वसूली की गई (सारणी 25)।

तालिका 25: 30 सितंबर, 2021 तक परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति

परिसमापन की स्थिति	संख्या
परिसमापन आरम्भ	1419*
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत#	264
समाधान द्वारा बंद	151
गोइंग कंसर्न सेल द्वारा बंद	6
समझौता / व्यवस्था	7
परिसमापन प्रक्रिया चल रही है**	1155
> दो वर्ष	456
> एक वर्ष ≤ दो वर्ष	333
> 270 दिन ≤ 1 वर्ष	80
> 180 दिन ≤ 270 दिन	156
> 90 दिन ≤ 180 दिन	74
≤ 90 दिन	56

स्रोत: आईबीबीआई 2021

नोट: \* इसमें 12 मामले शामिल नहीं हैं जहां एनसीएलटी / एनसीएलएटी / एचसी / एससी द्वारा परिसमापन आदेश को अलग रखा गया है; # इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां एनसीएलटी के पास जल्दी विघटन के लिए एक आवेदन दायर किया गया है; \*\* इसमें 3 मामले शामिल हैं जहां सीडी को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में बेचा गया है, हालांकि, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा की जा रही है।

### (ग) समय और लागत

4.60 421 सीआईआरपी, जिन्होंने सितंबर 2021 के अंत तक समाधान योजनाएं प्राप्त की हैं, प्रक्रिया के समापन के लिए औसतन 428 दिन (निर्णायक प्राधिकारी द्वारा छोड़े गए समय को छोड़कर) लगे। इसमें से 388 सीआईआरपी के संबंध में लागत विवरण उपलब्ध है। 'लागत' परिसमापन मूल्य का औसतन 0.98 प्रतिशत और समाधान मूल्य का 0.54 प्रतिशत आती है।

4.61 1419 सीआईआरपी, जो परिसमापन के आदेश में समाप्त हुए, में औसतन 375 दिन लगे। इसके अलावा, 264 परिसमापन प्रक्रियाएं, जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से बंद हो गई हैं, को बंद होने में औसतन 427 दिन लगे।

### (ड) व्यवहार परिवर्तन

4.62 संकटग्रस्त परिसंपत्ति का एक जीवन चक्र होता है और इसका मूल्य समय के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है। तथ्य यह है कि संकट में एक कॉर्पोरेट देनदार व्यवसाय को किसी अलग स्वामी के हाथ में दे सकता है, जिससे देनदारों का व्यवहार बदल जाता है। हजारों कर्जदार संकट के शुरुआती चरणों में संकट का समाधान कर रहे हैं, या तो जब व्यतिक्रम निकट होता है, चुकौती के लिए एक नोटिस प्राप्त होने पर, आवेदन दाखिल करने से पहले, आवेदन दाखिल करने के बाद लेकिन इसके प्रवेश से पहले, और आवेदन के प्रवेश के बाद भी, और समाधान प्रक्रिया के परिणामों से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किया जा रहा है। सितंबर 2021 तक, 5,89,516 करोड़ रुपये के अंतर्निहित डिफॉल्ट वाले सीडी के सीआईआरपी शुरू करने के लिए 18,629 आवेदनों को उनके प्रवेश से पहले समाधान किया गया था। इसके अलावा, सितंबर 2021 तक संहिता की धारा 12A के अंतर्गत कुल 527 सीआईआरपी वापस ले लिए गए हैं। इनमें से लगभग तीन चौथाई सीआईआरपी में ₹ 10 करोड़ से कम के दावे थे और 701 सीआईआरपी मामलों को अपील/समीक्षा/निपटान पर बंद कर दिया गया है।

### कॉर्पोरेट एमएसएमई के लिए दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी) और दिवाला समाधान प्रक्रिया (प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन)

4.63 तनाव के समाधान के लिए कई प्रतिस्पर्धी विकल्पों का प्रावधान अर्थव्यवस्था को व्यापार करने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। इस विचार के अनुरूप, दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2016 को 4 अप्रैल, 2021 को एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिससे वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के रूप में कॉर्पोरेट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक प्री-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया (PPIRP) प्रदान की जा सके और त्वरित परिणाम सुनिश्चित किए जा सके।

4.64 पीपीआईआरपी(PPIRP) में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) की कठोरता और अनुशासन है। यह एक बिंदु तक अनौपचारिक है और उसके बाद औपचारिक है। यह 'देनदार-का-कब्जा और नियंत्रण में लेनदार' का मिश्रण है। यह न तो पूरी तरह से निजी है और न ही पूरी तरह से सरकारी प्रक्रिया है - यह कंपनी को, यदि कंपनी धारा 29A के अंतर्गत पात्र है, मूल समाधान योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, जो मूल्य अधिकतमकरण के लिए चुनौती के प्रभाव में है। यह दिवाला समाधान प्रक्रिया(CIRP) जितनी ही हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करता है और किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त जाँच और संतुलन रखता है। इस प्रक्रिया में अदालतों और दिवाला पेशेवरों की सीमित भूमिका होती है।

4.65 प्रारंभ से पहले के चरण में अनौपचारिकता सीडी और उसके लेनदारों को व्यापार में तनाव को हल करने के सर्वोत्तम तरीके का तेजी से पता लगाने और बातचीत करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है, जबकि प्रारंभ के बाद का चरण मूल्य को अधिकतम करता है और वैधानिक सुरक्षा के साथ समाधान योजना प्रदान करता है। शुरू होने की तारीख से, प्रक्रिया को 120 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरा करना आवश्यक है। पीपीआईआरपी के दौरान, सीडी के मामलों का प्रबंधन निदेशक-मंडल/सीडी के भागीदारों में निहित होता है, समाधान व्यावसायिक(रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) लेनदारों के मार्गदर्शन और निगरानी में प्रक्रिया का संचालन करता है।

**बॉक्स 6: कॉर्पोरेट्स के लिए स्वेच्छया परिसमापन प्रक्रिया**

दिवाला या शोधन-अक्षमता के मामले में परिसमापन अस्वैच्छिक हो सकता है; या स्वेच्छया जो व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है, इसमें सहायक कंपनियों का विलय आदि हो सकता है। एक कंपनी व्यवहार्य होने पर भी स्वेच्छा से अपना संचालन बंद करने का निर्णय ले सकती है। दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) की प्रारंभ के साथ दिवाला/शोधन-अक्षमता के कारण समापन की प्रक्रिया में एक बदलाव आया है। हालांकि, हाल की प्रगति के शीर्ष पर, व्यवसाय के स्वैच्छिक निकास की प्रक्रिया को अभी भी महत्वपूर्ण रूप से सरल बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, स्वेच्छया परिसमापन की दो मुख्य विधियाँ हैं, पहली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार(आरओसी) के माध्यम से है और दूसरी आईबीसी के अंतर्गत है। पहली विधि वर्तमान में अब तक की अधिक लोकप्रिय विधि है।

**i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2)**

कंपनी अधिनियम की धारा 248(2) के अंतर्गत, कंपनी अपनी सभी देनदारियों को समाप्त करने के बाद, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को विशेष समाधान या 75 प्रतिशत सदस्यों की सहमति से चुकता शेयर पूंजी के संदर्भ में एक निर्धारित तरीके से आवेदन दायर कर सकती है। कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए। अनुबंध 1 धारा 248(2) के अंतर्गत स्वेच्छया परिसमापन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है।

**चरण 1 :** कंपनी को बैंक खाते को बंद करने की मंजूरी देने के लिए सभी लंबित देनदारियों का भुगतान करने के लिए एक बोर्ड बैठक बुलानी होगी, और बैंक खाता बंद होने के बाद कंपनी का नवीनतम वित्तीय विवरण तैयार करना होगा।

**चरण 2: कंपनी संबंधित आरओसी में एसटीके (STK)-2 फॉर्म फाइल करती है**

**चरण 3:** निदेशक ई-फॉर्म में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें कहा गया है कि कंपनी के पास किसी भी सरकारी विभाग (केंद्र, राज्य, वैधानिक या स्थानीय प्राधिकरण) के प्रति कोई बकाया नहीं है। इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट या कंपनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

**चरण 4:** एमसीए वेबसाइट, राजपत्र और सबसे बड़े परिसंचारी समाचार-पत्र(एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में हो) में एक निर्धारित विधि से आरओसी द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। किसी भी दावे और आपत्ति को करने के लिए 30 दिनों का नोटिस समय प्रदान किया जाता है। यदि समापन के लिए आवेदन करने वाली कंपनी विशेष अधिनियम (धारा 8 के तहत) के अंतर्गत विनियमित है, तो संबंधित नियामक निकाय के अनुमोदन की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं<sup>8</sup> है।

**चरण 5:** नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद, आरओसी कंपनियों के नाम को काट सकता है और आधिकारिक राजपत्र में विघटन/समाप्ति नोटिस प्रकाशित कर सकता है।

इसे एक तेज समापन प्रक्रिया माना जाता है; तथापि, यह देखा गया कि बड़ी संख्या में लम्बित मामले थे। 13 जून 2021 तक, 28,536 लंबित मामलों में से, लगभग 10 प्रतिशत मामले 1000 दिनों से अधिक से लंबित थे और 54 प्रतिशत मामले (15,310) एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे, इसके बाद, सरकार द्वारा पिछले मामलों के ढेर(बैकलॉग) को दूर करने के प्रयास किए गए थे। आवेदनों की। परिणामस्वरूप, लंबित मामलों की संख्या 10 जनवरी 2022 तक 9,768 हो गई है, जिनमें से केवल 16.3 प्रतिशत ही एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, फिर भी इस प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकता है।

<sup>8</sup> एसी कंपनियों के लिये, जोकि व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निगमित की गई हैं जैसे कि एन बी एफ सी, असेट मैनेजमेंट कंपनियाँ, बीमा आदि, अपने विनियामक प्राधिकरणों जैसेकि आरबीआई, सेबी, आईआरडीए से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है।

## ii. दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता ( आईबीसी )

दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 59 आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 (स्वैच्छिक परिसमापन विनियम) के साथ एक कॉर्पोरेट व्यक्ति के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए तंत्र प्रदान करती है। आईबीसी की धारा 59 में कहा गया है कि 'एक कॉर्पोरेट व्यक्ति जो स्वेच्छा से खुद को समाप्त करने का इरादा रखता है और कोई चूक नहीं करता है, वह इस अध्याय के अंतर्गत स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकता है'। सितंबर 2021 तक इस योजना के अंतर्गत अब तक 1042 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और इनमें से 483 मामलों की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और 257 मामलों में निराकरण का अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, अर्थात् लगभग 25 प्रतिशत मामलों को विघटित/भंग करके बंद कर दिया गया है। चल रहे मामलों में से। परिसमापन के लगभग 32 प्रतिशत मामले 2 वर्ष से अधिक और 19 प्रतिशत 1 से 2 वर्ष के बीच लंबित हैं (तालिका 6क)।

तालिका 6क: सितंबर 30, 2021 तक स्वैच्छिक परिसमापन की स्थिति

स्थिति	परिसमापन की संख्या
आरंभ की गई	1042
वापसी	10
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत	483
भंग/विघटन द्वारा बंद	257
जारी	549
> दो साल	177
> एक साल ≤ दो साल	104
> 270 दिन ≤ 1 वर्ष	61
> 180 दिन ≤ 270 दिन	107
> 90 दिन ≤ 180 दिन	35
≤ 90 दिन	65

स्रोत: आईबीबीआई

**आई.बी.सी. के तहत स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया की चरण-दर-चरण प्रक्रिया इस प्रकार है:**

**चरण 1:** स्वैच्छिक परिसमापन को मंजूरी देते हुए एक बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है। संहिता की धारा 59(3)(ए) में प्रावधान है कि कंपनी के अधिकांश निदेशक सॉल्वेंसी और किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए कंपनी का परिसमापन नहीं होने के संबंध में एक घोषणा पारित करेंगे। इस घोषणा के साथ 2 मर्दों को देना होगा:

(क) पिछले दो वर्षों के लिए या इसके निगमन के बाद से, जो भी बाद में हो, कंपनी के वित्तीय विवरण और कंपनी के व्यापार संचालन का लेखा-जोखा।

(ख) एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार कंपनी की संपत्ति, यदि कोई हो, के मूल्यांकन की एक रिपोर्ट।

**चरण 2:** शेरधारक के संकल्प को पारित करना और एक परिसमापक की नियुक्ति करना। एक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों का एक संकल्प (या विशेष संकल्प) होगा जिसमें कंपनी को स्वेच्छा से परिसमाप्त करने और परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए एक दिवाला पेशेवर की नियुक्ति की आवश्यकता होगी। कंपनी के ऋण के मूल्य में दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदार ऐसे संकल्प के सात दिनों के भीतर उक्त संकल्प को मंजूरी देंगे।

**चरण 3:** परिसमापक स्वैच्छिक परिसमापन विनियमों के संहिता और विनियम 3 (2) के अनुसार सात दिनों के भीतर भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) और आरओसी को संकल्प फाइल करता है। स्वैच्छिक

परिसमापन विनियमों के विनियम 14 में 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक घोषणा (अंग्रेजी और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में) करने की आवश्यकता होती है, जिसमें हितधारकों को 30 दिनों के भीतर दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है (संहिता की धारा 38 (1))।

**चरण 4:** नकद और तरल निधियों के लिए एक निर्दिष्ट बैंक खाता खोलना और मौजूदा बैंक खाते को बंद करना और एक निर्दिष्ट बैंक खाते में धन का हस्तांतरण करना।

**चरण 5:** केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और क्षेत्रीय नियामकों में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन करें (इन एनओसी का आईबीसी में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन लिया जाना निहित है)।

**चरण 6:** परिसमापक शेयरधारकों को अंतिम विप्रेषण देता है। इसके अलावा परिसमापक जमा करों को रोकते हैं और फिर परिसमापन के लिए खोले गए बैंक खाते को बंद कर देते हैं।

**चरण 7:** परिसमापक फिर शेयरधारकों, आरओसी, आईबीबीआई और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

**चरण 8:** एनसीएलटी द्वारा आदेश पारित किया जाता है।

**चरण 9:** आरओसी से कॉर्पोरेट देनदार के नाम को हटाने के लिए फॉर्म आईएनसी 28 और आरओसी के साथ आरओसी के साथ कॉर्पोरेट देनदार के विघटन के आदेश की फाइल कॉपी।

इस प्रक्रिया में पहला प्रमुख मुद्दा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य क्षेत्रीय नियामकों सहित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में देरी है। एनओसी लेने के लिए निहित हैं, हालांकि संहिता में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इससे विभागों, परिसमापकों आदि के बीच पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सही प्रक्रिया के संबंध में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इस प्रक्रिया में एक और मुद्दा यह है कि एनओसी देने के लिए विभागों में कोई अच्छी तरह से परिभाषित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नहीं है। वर्तमान प्रथा के अनुसार, परिसमापक विभागों के प्रमुख को एक पत्र लिखते हैं जिसमें विभाग के कंपनी पर किसी भी दावे के लिए और एनओसी प्रदान करने के लिए कहा जाता है। विभाग तब आवेदन का आकलन करता है और जवाब देता है। चूंकि कोई एसओपी नहीं है, इसलिए विभागों द्वारा किए गए दावे विलंब से आते हैं और निर्धारित अवधि के भीतर नहीं होते हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में देरी के कारण एक और समस्या यह है कि एनसीएलटी बैंक द्वारा आवश्यकताओं पर कोई मानक दिशानिर्देश नहीं हैं, प्रक्रियाओं में अंतराल पैदा कर रहा है क्योंकि कंपनी को एनसीएलटी द्वारा आवश्यक निर्दिष्ट मंजूरी लेने के लिए विभिन्न विभागों से संपर्क करना पड़ता है। एक अन्य मुद्दा मौजूदा बैंक खातों को बंद करने और परिसमापक द्वारा नया परिसमापन बैंक खाता खोलने के लिए बैंकों में झिझक है, जो परिसमापन कार्यवाही में एक अनिवार्य कदम है।

संक्षेप में, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया में समस्याओं को सरल बनाने, व्यापार के लिए निकास की आसानी में सुधार करने का मामला है। प्रक्रियाओं में विभिन्न चरणों में मुद्दों को सरल बनाने के अलावा, पूरी प्रक्रिया के लिए एकल खिड़की के निर्माण की आवश्यकता है। एक पोर्टल जो परिसमापन प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरी तरह से जोड़ता है, कंपनियों द्वारा आवेदन से लेकर सभी विभागों द्वारा प्रसंस्करण तक बहुत उपयोगी साबित होगा।

## सीमा पार दिवाला

4.66 सीमा पार दिवाला उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिसमें एक दिवालिया देनदार के पास एक से अधिक देशों में आस्तियों और/या लेनदार होते हैं। आमतौर पर, घरेलू कानून देनदारों की आस्तियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं; आस्तियों मांगना और उन्हें मौद्रिक रूप में परिवर्तित करना; घरेलू लेनदारों/देनदारों के लिए उचित प्राथमिकता आदि के अनुसार लेनदारों को वितरण करना। हालांकि, ऐसे कई दिवाला मामले हैं जिनमें निगमों पर एक से अधिक देशों में आस्ति और देनदारियां बकाया हैं।



4.67 वर्तमान में, शोधन-अक्षमता और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में दिवालिया उद्यम के प्रबंधन के लिए घरेलू कानूनों का प्रावधान है। वर्तमान में, आईबीसी के पास सीमा पार क्षेत्राधिकारों से जुड़ी फर्मों के पुनर्गठन के लिए कोई मानक लिखत नहीं है। सीमा पार प्रबंधन का स्वरूप नहीं होने की समस्या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा मुंबई में एक भारतीय संस्था से जुड़े सीमापार दिवाला मामले में भी जताई थी। एनसीएलटी ने कहा कि नीदरलैंड की एक जिला अदालत के समक्ष कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है, “आईबीसी में इस समय किसी भी विदेशी राष्ट्र की दिवालिया अदालत के फैसले को मान्यता देने का कोई प्रावधान और तंत्र नहीं है। इस प्रकार, भले ही विदेशी न्यायालय के निर्णय का सत्यापन किया जाता है और यह सही पाया जाता है, फिर भी, आईबीसी में प्रासंगिक प्रावधान के बिना, हम इस आदेश को रिकॉर्ड में नहीं ले सकते।” मानकीकृत सीमा पार दिवाला ढांचा नहीं होने से जटिलताएं पैदा होती हैं और विभिन्न मुद्दे उठते हैं; जैसे:

- कोई शोधन-अक्षमता प्रशासक किसी विदेशी देश में रखी गई आस्तियों तक किस सीमा तक पहुंच प्राप्त कर सकता है।
- भुगतान की प्राथमिकता - क्या विदेशी प्रशासन के पास निधियों के जाने से पहले स्थानीय लेनदारों को स्थानीय आस्तियों तक पहुंच हो सकती है या नहीं।
- एक विदेशी प्रशासन में स्थानीय लेनदारों के दावों की मान्यता।
- स्थानीय प्रतिभूतियों की मान्यता और प्रवर्तन, स्थानीय परिसंपत्तियों पर कराधान प्रणाली जहां एक विदेशी प्रशासक नियुक्त किया जाता है; आदि।

4.68 वर्तमान में, विदेशी लेनदार किसी घरेलू कंपनी के खिलाफ दावे कर सकते हैं, परंतु आईबीसी वर्तमान में अन्य देशों में किसी भी दिवाला कार्यवाही की स्वतः मान्यता की अनुमति नहीं देता है। क्रॉस बॉर्डर इनसॉल्वेंसी को आईबीसी की धारा 234 और 235 (विवरण के लिए अनुलग्नक देखें) द्वारा विनियमित किया जाता है। धारा 234 केंद्र सरकार को सीमा पार शोधन-अक्षमता के बारे में स्थितियों को सुलझाने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण समझौते (धारा 234 के अंतर्गत) में शामिल देशों की संहिता के तहत दिवालिया कार्यवाही के संबंध में साक्ष्य या कार्रवाई के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम अदालत या प्राधिकरण (धारा 235 के तहत) को अनुरोध पत्र जारी कर सकता है।

4.69 जैसा कि देखा जा सकता है, आईबीसी के तहत वर्तमान प्रावधान तदर्थ प्रकृति के हैं और उन प्रावधानों के तहत विलम्ब होने की बहुत अधिक संभावना होती है। पारस्परिक (व्युत्क्रम) समझौते करने के लिए प्रत्येक देश के साथ व्यक्तिगत रूप से लंबी वार्ताओं की आवश्यकता होती है। इससे लेनदारों, देनदारों और अन्य हितधारकों के दावों का कच्चा परिणाम होगा, इसकी अनिश्चितता हो जाती है।

4.70 इसलिए सीमा पार शोधन-अक्षमता के लिए एक मानकीकृत संरचना की आवश्यकता है। यह मुद्दा नया नहीं है और वस्तुतः *इन्सॉल्वेंसी लॉ कमेटी (आईएलसी)* (अक्टूबर 2018) की रिपोर्ट में एक सुदृढ़ सीमापार ऋणशोधन अक्षमता संरचना तैयार करने के प्रस्ताव पर पहले ही ध्यान दिलाया गया है। समिति ने संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूएनसीआईट्राएल) को भारतीय संदर्भ में उपयुक्त बनाने के लिए कुछ संशोधनों के साथ अपनाने की सिफारिश की थी। वास्तव में, सीमापार शोधन-अक्षमता मुद्दे के समाधान के लिए सीमापार शोधन-अक्षमता, 1997 से संबंधित यूएनसीआईटीआरएएल सबसे बड़े पैमाने पर स्वीकार्य कानूनी

<sup>9</sup> भारतीय स्टेट बैंक ट जैट एयरवेज (इंडीया) लिमिटेड CP2205 (IB) / MB / 2019, CP1968 (IB) /MP/2019, CP1938 (IB)/MB/2019, आदेश दिनांक 20 जून 2019

संरचना के रूप में उभरा है। यह एक विधायी संरचना प्रदान करता है जिसे अधिनियमित क्षेत्राधिकार के घरेलू संदर्भ के अनुरूप कुछ संशोधनों के साथ देशों द्वारा अपनाया जा सकता है। इसे अब तक 49 देशों ने अपनाया है, जैसे सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया आदि। यह कानून चार मुख्य सिद्धांतों की मदद से सीमा पार शोधन-अक्षमता मामलों के मुख्य मुद्दों का समाधान करता है:

- **पहुंच:** यह विदेशी पेशेवरों और लेनदारों को घरेलू अदालतों तक सीधी पहुंच की अनुमति देता है और उन्हें एक देनदार के खिलाफ घरेलू शोधन-अक्षमता कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाता है।
- **मान्यता:** यह विदेशी कार्यवाहियों की मान्यता की अनुमति देता है और अदालतों को तदनुसार राहत निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।
- **सहयोग:** यह दिवाला पेशेवरों और देशों की अदालतों के बीच सहयोग के लिए एक संरचना प्रदान करता है।
- **समन्वय:** यह विभिन्न नयायालयों में सहमत होने वाली 'समवर्ती कार्यवाहियों' को संचालित करने की अनुमति देता है।